अब वेब पर भी www.rashtriyaprastavana.com

उत्तर प्रदेश (लखनऊ व कानपुर) से एक साथ प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र

आर.एन.आई. नं.-यूपीएचआईएन/2011/37605

दैनिक राष्ट्रीय प्रस्तावना

गाँव से गवर्नेन्स तक

लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद,आजमगढ़, अयोध्या, झांसी,अम्बेडकरनगर, एटा,औरैया, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव, लखीमपुर, मुरादाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, सीतापुर,जौनपुर,श्रावस्ती,उरई,जालौन, फिरोजाबाद,हरदोई, मथुरा,कानपुर,ललितपुर, गोण्डा, सहारनपुर,सिद्धार्थनगर,सन्तकबीरनगर, नोयडा, सुलतानपुर, कासगंज सहित प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में बहुप्रसारित

वर्ष : 15 अंक 207 लखनऊ, गुरुवार, 12 फरवरी 2026 पृष्ठ: 8 मूल्य : 2.00

संक्षिप्त

भाजपा की रितु तावड़े बनीं मुंबई की नई मेयर, शिवसेना के संजय घाड़ी बने उप महापौर

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पार्षद रितु तावड़े बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की निर्विरोध महापौर चुनी गई हैं। वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद संजय घाड़ी उपमहापौर बने हैं। इसकी घोषणा बुधवार को बीएमसी मुख्यालय में निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने की। आयुक्त गगरानी ने कहा कि महापौर पद के लिए केवल भाजपा पार्षद रितु तावड़े का ही नामांकन प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें बीएमसी का महापौर घोषित किया जाता है। इसी तरह, उपमहापौर पद के लिए केवल संजय घाड़ी का ही नामांकन प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें उपमहापौर घोषित किया जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने रितु तावड़े और संजय घाड़ी को शुभकामनाएं दीं।

अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों और क्रिस (सीआरआईएस) के प्रबंध निदेशक को निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार, पूर्व में 15 जनवरी के निर्देशों के तहत इन ट्रेनों में केवल महिला कोटा, दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) कोटा, वरिष्ठ नागरिक कोटा और ड्यूटी पास कोटा ही लागू था तथा अन्य किसी प्रकार का आरक्षण कोटा, जिसमें आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) भी शामिल है, लागू नहीं था। मामले की समीक्षा के बाद अब इन ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उप्र सरकार ने पेश किया 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट

बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय, शिक्षा-स्वास्थ्य और कृषि पर योगी सरकार का विशेष फोकस

- नव निर्माण के नौ वर्ष की थीम पर प्रस्तुत बजट में 43,565 करोड़ रुपये की नई योजनाएं
- बजट में प्रदेश सरकार का वित्तीय अनुशासन के साथ समग्र विकास पर भी फोकस
- राजकोषीय घाटा 2.98% पर नियंत्रित, राजस्व बचत 64,457 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 2.48 लाख करोड़ रुपये निर्धारित
- स्वच्छताकर्मियों को सीधे अकाउंट में मिलेंगे 16 से 20 हजार रुपये, बजट में किया गया प्रावधान

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया।

नव निर्माण के नौ वर्ष की थीम पर प्रस्तुत बजट 2026-27 का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। आकार के लिहाज से योगी सरकार ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को बताया कि यह बजट राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता, निवेश के अनुकूल माहौल और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है। यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। बजट 2026-27 सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी तीनों को समान महत्व दिया गया है। इस बजट में अन्नदाता किसान, युवा, महिला, छात्र-छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 19.5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना को नई गति देगा।

पूंजीगत निवेश से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों को बजट में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल बजट का 12.4 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 6 प्रतिशत और कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 9 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मानव संसाधन विकास और किसानों की आय बढ़ाने को विकास की धुरी मानकर चल रही है।

उन्होंने बताया कि 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राजकोषीय अनुशासन से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 1,18,480.59 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत है। यह 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है और वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों तथा पीएम पोषण योजना की रसोइयों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए 357.84 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 89.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्कूल उपस्थिति में सुधार की उम्मीद है।

एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉइमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादों को पहचान और बाजार मिलेगा। इसके साथ ही, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

डीजल से सोलर की ओर बड़ा कदम

बजट में विशेष रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 637.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और एफपीओ को मजबूती

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का कोष नाबार्ड की सहभागी संस्था 'नैब किसान' के साथ मिलकर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार 75 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। प्रत्येक पात्र एफपीओ को अधिकतम 50 लाख रुपये तक की ऋण सीमा उपलब्ध कराई जाएगी।

यूपी एआई मिशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' (यूपीएआई मिशन) शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर 2.0 के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और लखनऊ में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य जनपदों (अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर एवं मुरादाबाद) में विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एसजीपीजीआई में क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सुविधा प्रारंभ करने के लिए 359 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना: वाराणसी रीजन चयनित

केन्द्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना में 7 रीजन की पहचान की गई है, जिनमें वाराणसी रीजन भी शामिल है।

जनाकांक्षाओं के अनुरूप, जनकल्याणकारी, रोजगार सृजन वाला बजट : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बजट को प्रदेश की जनाकांक्षाओं के अनुरूप, जनकल्याणकारी, रोजगार सृजन, निवेश में विस्तार और महिलाओं के सम्मान देने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की छवि बीमारु प्रदेश से बदल कर विकसित उत्तर प्रदेश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा के तिलक हाल में बजट को लेकर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में परसेप्शन बदला है और यह बजट तीन गुना बढ़ा है। यह बजट सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसाल, हर हाथ को काम तकनीक आगे कर नवनिर्माण की गाथा को लिखता है। इसमें नई योजनाओं के लिए लगभग 43 हजार करोड़ रुपये और दो लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत रोजगार, कौशल विकास के लिए प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज प्रस्तुत किया गया बजट हमारी सरकार का 10वां बजट है और यूपी जैसे राज्य में पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने लगातार 10वां बजट पेश किया है। सबसे खास बात यह कि इस दौरान नौ सालों में हमने कोई टैक्स वृद्धि नहीं की। उत्तर प्रदेश के बजट को जनाकांक्षाओं के अनुरूप बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि इसे बीमारु प्रदेश के नाम से जाना था लेकिन हमने प्रदेश की छवि बदली है। प्रत्येक सेक्टर में नई उचाइयों को छुआ है और कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण आज देश की टॉप तीन अर्थव्यवस्थाओं में से उत्तर प्रदेश एक है। वर्ष 2017 पहले बेरोजगारी की दर 17 से 19 फीसदी थी लेकिन हमारी सरकार इस दो फीसदी से नीचे ले आयी है। यह बजट युवाओं के लिए समर्पित है,जिसमें रोजगार का सृजन, एमएसएमई को बढावा दिया जा रहा है।

चुनाव से पहले आयोग का बड़ा आदेश

तीन साल से एक ही जगह तैनात अधिकारियों का होगा तबादला

एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पद या जिले में तैनात प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है। बुधवार को आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

निर्देश के अनुसार यह आदेश जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, उप-मंडलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा।

इसके साथ ही पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), उप-महानिरीक्षक (डीआईजी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी स्थानांतरित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिन अधिकारियों ने किसी विशेष जिले या पद पर तीन वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है, उन्हें स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा।

हालांकि, राज्य मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। आयोग ने मुख्य सचिव को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भेज दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो अधिकारी किसी जिले में जिलाधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे उन्हें आगामी चुनाव में उसी जिले में दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा।

कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को बेच या खरीद सके: रीजीजू

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को बेच या खरीद सके। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पूरी तरह समर्पण कर दिया है और ''उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है।'' इसपर रीजीजू ने कहा, ''मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, जो भारत को बेच सकता है और खरीद सकता है।'' उन्होंने कहा, ''मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं।

योगी सरकार का बजट निराशाजनक : विपक्ष

- भाजपा सरकार का आखिरी और विदाई बजट है: अखिलेश

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आम जनता बजट को लेकर विपक्षी दलों ने आम जनता और युवाओं, किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों के लिए सूखा और खाली बताते हुए विदाई वाला बताया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला करार दिया है।

कांग्रेस पार्टी और सदन में विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने उत्तर प्रदेश के आम बजट में कुछ भी नया न होना वाला

बताया। उन्होंने कहा कि ये सूखा और खाली बजट है। इसमें युवाओ, किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों सहित सभी को निराश करने वाला है। योगी सरकार का ये अंतिम बजट है। इतने बड़े बजट में सिर्फ 5 प्रतिशत भी नई योजनाएं नहीं है। 9 लाख 12 हजार करोड़ में सिर्फ 43 करोड़ की नई योजनाएं, बहुत निराशाजनक है। वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए जनता की जेब काटने की तैयारी में भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार का यह बजट पेश किया गया है।

कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बजट को लेकर कहा कि भाजपा की योगी सरकार हर बार बजट को अच्छा बताती है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर हुआ। कोई एक काम ऐसा नहीं हुआ जिससे प्रदेश के नागरिकों को भाग्य बदल गया हो। लोगों को अच्छी सुविधाएं मिली हों। मथुरा में पूरा परिवार आर्थिक स्थिति के कारण सुसाइड कर लिया। पिछला बजट कहां खर्च हुआ, उस पर स्वेत पत्र जारी कर सरकार बताए।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पेश बजट को विदाई वाला करार दिय। उन्होंने कहा कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है ये माना जाता है। पिछले से इस बजट की तुलना करें तो बड़ा है, लेकिन खर्च नहीं कर पा रही योगी सरकार। जो एमओयू हुए थे वो जमीन पर कितना पहुँचा। डील के बाद एमएसएमई में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि इसके साथ भाजपा की विदाई तय है। लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के पेश बजट केवल घोषणाओं का पुलिंदा बताया। उन्होने कहा कि बजट का जमीनी सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है।

मतदाताओं के पास हो 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार : राघव चड्ढा

एजेंसी

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने काम नहीं करने की स्थिति में जन प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को दिए जाने, प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुए बड़े हादसों और अभिभावकों की वृद्धावस्था में देखभाल न किए जाने जैसे मुद्दे उठाए तथा सरकार से अपेक्षित कदम उठाने का अनुरोध किया। शून्यकाल में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि जिस तरह मतदाताओं को मतदान का अधिकार है उसी तरह, काम नहीं करने की स्थिति में 'राइट टू रिकॉल' (जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार) भी

मतदाताओं के पास होना चाहिए।

चड्ढा ने कहा ''अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को चुन सकता है तो उसे उन्हें काम न करने पर हटाने का हक भी होना चाहिए। 'राइट टू रिकॉल' व्यवस्था मतदाताओं को अधिकार संपन्न बनाएगी ताकि अगर जन प्रतिनिधि काम न करे तो उसे हटाया जा सके।''

उन्होंने कहा कि सांसद या विधायक चुने जाने के बाद अगर जन प्रतिनिधि काम न करे तो जनता के पास पांच साल तक बर्दाश्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ''गलत नेता को चुनने के एक गलत फैसले से पूरा क्षेत्र, पूरा समय बर्बाद होता है और लाखों मतदाता इसका खामियाजा भुगतते हैं।''

- चड्ढा ने कहा ''अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को चुन सकता है तो उसे उन्हें काम न करने पर हटाने का हक भी होना चाहिए

चड्ढा ने स्पष्ट किया कि 'राइट टू रिकॉल' नेताओं के खिलाफ हथियार नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि 'राइट टू रिकॉल' के तहत मतदाता एक निर्धारित और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। चड्ढा ने कहा कि भारत में पहले ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की व्यवस्था है और सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

उन्होंने दावा किया कि अमेरिका, स्विटजरलैंड और कनाडा सहित दुनिया के 20 से अधिक लोकतांत्रिक देशों में 'राइट टू रिकॉल' की व्यवस्था है। हमारे देश में कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था है।''

भारत 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा: सरकार

- 2030 तक 5जी उपभोक्ता 100 करोड़ होने का अनुमान

एजेंसी

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि वाई-फाई कनेक्टिविटी की 4जी तकनीक में भारत विश्व के पीछे था, 5जी में विश्व के साथ चला है और 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा, यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह

भी कहा कि अभी देश में 5जी कनेक्टिविटी के उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ है और 2030 तक यह आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की मिताली बाग के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, '' वाई-फाई कनेक्टिविटी की 4जी तकनीक में भारत विश्व के पीछे था, 5जी में विश्व के साथ चला है और 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा, यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है।'' उन्होंने कहा कि भारत में 5जी तकनीक का क्रियान्वयन पूरी दुनिया में सबसे तेजी से हुआ है और 22 महीने में देशभर में इसे लागू कर दिया गया। सिंधिया ने कहा, ''आज देश के 99.9 प्रतिशत जिलों में 5जी लागू है। आज देश में 40 करोड़ लोग 5जी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और 2030 में यह संख्या 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सामाजिक समरसता व सुशासन को सुदृढ़ आयाम देने वाला है बजट : राज्यपाल

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदन में प्रस्तुत राज्य सरकार के बजट 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे समावेशी, दूरदर्शी एवं जनोन्मुखी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं के सशक्तीकरण, सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार एवं डिजिटल सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया जाना अत्यंत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उपलब्ध कराया जाना प्रदेश की उदीयमान शक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था तथा मुख्यमंत्री फ़ेलोशिप कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नीति निर्माण में सहभागिता का अवसर देना, सुशासन की सशक्त पहल है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण को डिजिटल क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही, युवाओं के खेल एवं शारीरिक विकास के लिए मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराए जाने को सकारात्मक पहल कहा।

राज्यपाल ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि अपराधों में उल्लेखनीय कमी तथा पुलिस अधोसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रावधान, जनसामान्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की सजगता को दर्शाते हैं। नवसृजित जनपदों में पुलिस भवनों के निर्माण, अग्निशमन सेवाओं के विस्तार महत्वपूर्ण हैं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय बजटीय प्रावधानों की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या एवं एमबीबीएस तथा पीजी सीटों में वृद्धि से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, कैंसर संस्थान के लिए प्रावधान तथा असाध्य रोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सामाजिक समरसता और सुशासन को सुदृढ़ करते हुए उत्तर प्रदेश को प्रगति के नए आयामों तक ले जाएगा।

भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं संस्थापक आचार्य राम महेश मिश्र का लखनऊ में भव्य सम्मान

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं संस्थापक आचार्य राम महेश मिश्र का राजधानी लखनऊ में हुआ भव्य सम्मान। श्री मिश्र को यह सम्मान विचार क्रान्ति एवं आध्यात्मिक जगत की विभिन्न सराहनीय गतिविधियों तथा हिन्दी साहित्य जगत में सक्रिय योगदान के लिए दिया गया। सरोजिनीनगर लखनऊ से यशस्वी विधायक श्री राजेश्वर सिंह द्वारा यह सम्मान उन्हें आशियाना परिवार लखनऊ के वार्षिक कार्यक्रम में दिया गया। ज्ञातव्य हो, श्री सिंह आईपीएस अधिकारी के रूप में गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के संयुक्त निदेशक रहे हैं। इस अवसर पर हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई आदि धर्मों के प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद थे। आशियाना परिवार के अध्यक्ष आर. डी. द्विवेदी तथा विभिन्न संगठनों के प्रमुखों ने आचार्य मिश्र को बधाई दी। इस अवसर पर सभी को भाग्योदय फाउंडेशन की पुस्तक ''समग्र व्यक्तित्व निर्माण एवं सफल जीवन के 108 महत्वपूर्ण सूत्र'' भेंट की गई। विधायक श्री सिंह ने भारत के विकास में वैज्ञानिकों के अमूल्य योगदान से देश की नई पीढ़ी को परिचित कराने वाली पत्रिका 'भारत की विज्ञान यात्रा' की सराहना की।

आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित है उप्र का बजट : जयवीर सिंह

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बजट 2026-27 में पर्यटन और संस्कृति को प्राथमिकता दिए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का उत्तर प्रदेश बजट पेश किया। 9.13 लाख करोड़ रुपये के कुल आकार वाला यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.2 प्रतिशत अधिक है। बजट में बुनियादी ढांचे, जनकल्याण और विकासोन्मुखी क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें पर्यटन और संस्कृति प्रमुख फोकस के रूप में उभरे हैं। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में और मजबूत पहचान दिलाना है।

जयवीर सिंह ने जारी बयान में कहा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सरकार ने विरासत संरक्षण और राष्ट्रीय विभूतियों के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाया है। बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण कर लोकार्पित किया जा चुका है। रामनगर, वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय स्थापित कर आम जनता के लिए खोला गया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण पूर्ण कर लोकार्पित किया गया है। लखनऊ के ऐशबाग में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रयागराज में निषादराज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान दिया गया है।उन्होंने कहा कि पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रति विश्वास और आस्था का प्रमाण है। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वाराणसी में पर्यटकों की संख्या वर्ष 2024 में लगभग 11.01 करोड़ से बढ़कर 2025 में 17.30 करोड़ से अधिक हो गई। अयोध्या में यह संख्या 16.44 करोड़ से बढ़कर 29.95 करोड़ से अधिक पहुंच गई। मथुरा में 9.01 करोड़ से बढ़कर 10.24 करोड़ से अधिक, जबकि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व उपस्थिति दर्ज की गई। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2026 में चल रहे माघ मेले में अब तक 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मिर्ज़ापुर में पर्यटकों की संख्या 1.41 करोड़ से बढ़कर 2.10 करोड़ से अधिक और चित्रकूट में 1.18 करोड़ से बढ़कर 3.65 करोड़ से अधिक हो गई है। जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या, नैमिषारण्य, वाराणसी, विंध्याचल, मथुरा और प्रयागराज में बजट के माध्यम से किए गए विशेष प्रावधान पर्यटक सुविधाओं को और बेहतर बनाएंगे। इससे औसत प्रवास अवधि दो-तीन दिन से बढ़कर लगभग एक सप्ताह तक होने की संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पर्यटन सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला गाइड प्रशिक्षण हेतु लाइसेंस शुल्क माफ किया जाएगा, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

बजट उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को समर्पित : नरेंद्र कश्यप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बुधवार को यहां कहा कि योगी सरकार का यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को समर्पित है, जो उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्री कश्यप ने बताया कि योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 3,060 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 210 करोड़ रुपये तथा छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

योगी सरकार का बजट एमएसएमई, खादी और वस्त्रोद्योग को देगा नई गति : राकेश सचान

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि योगी सरकार का यह बजट प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंत्री सचान ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला एमएसएमई सेक्टर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और योगी सरकार इसे और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए एक हजार करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। ह्वनएक जनपद एक व्यंजनङ्क जैसी नई योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए लगभग 5,041 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पाँच गुने से अधिक है। वर्ष 2026-27 में वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना के अंतर्गत विश्वस्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4,423 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2022 के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों की स्थापना कर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपये बैंक ऋण की व्यवस्था की गई है। पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान के लिए 10 करोड़ रुपये तथा खजनी, गोरखपुर स्थित कम्बल उत्पादन केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए 7.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कॉर्पस फण्ड को लेकर भ्रम की स्थिति का हो निवारण : विजय बहादुर

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने बुधवार को सदन में नियम 110 के अंतर्गत कॉर्पस फण्ड को लेकर हुए भ्रम की स्थिति के निवारण तथा आर0डब्लू0ए0 और प्राधिकरण के बीच उत्पन्न हुए विवाद के समाधान कराये जाने की मांग की। सभापति कुंवर मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने सरकार को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। विजय बहादुर पाठक ने सदन में कहा कि विभिन्न प्राधिकारी क्षेत्रों में नयी आवासीय कालोनियां विकसित कर रही है, लोगों को बेहतर आवास मिले इस दिशा में कार्य भी हो रहा है। बड़े-बड़े अर्पाटमेंट बनाये जा रहे हैं। इनके रख रखाव के लिए जनकल्याण समितियां, रेसिडेंट वेल्फ़ेयर एसोशिएसन बने है। फ्लैटों में रहने वाले आवंटियों के कॉर्पस फण्ड को लेकर कई जगह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। गाजियाबाद, बरेली, नोएडा सहित कई महानगरों में रेसिडेंट वेल्फ़ेयर एसोशिएसन और प्राधिकरण के बीच में इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी है।

बजट सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर मजबूत कदम : दयाशंकर सिंह

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026ऽ27 के प्रदेश बजट में परिवहन विभाग के लिए किए गए प्रावधानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आमजन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को सशक्त करेगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए ई-बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये तथा बस अड्डों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा, यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा परिवहन तंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना के अंतर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटना पश्चात त्वरित कार्रवाई के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह प्रावधान सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाएगा। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे हरित ऊर्जा आधारित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदूषण में कमी आएगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ और सतत परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को आधुनिक परिवहन अवसंरचना से सुसज्जित करने, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस आधार प्रदान करेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत बजट का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल परिवहन सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सुलभ और तकनीक-सक्षम बनाकर आमजन के जीवन को सुगम बनाना है। यह बजट उसी संकल्प का प्रतिबिंब है।

जनकल्याण व जनआकांक्षाओं को समर्पित है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट: पंकज चौधरी

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को जनआकांक्षाओं को समर्पित, जनकल्याण, सुशासन और समृद्धि के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट बताते हुए बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 9.12 लाख करोड़ से अधिक का विशाल बजट पेश किया है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है, जिससे प्रदेश में विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं और अधिक गति से चलेंगी। प्रदेश सरकार ने विकास और विश्वास का जो मॉडल स्थापित किया है, यह बजट उसी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिम्ब है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है। मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु ठोस प्रावधान किए गए हैं, जिससे महिलाएं आर्थिक व सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए व्यापक योजनाएं इस बजट में सम्मिलित हैं, जो उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएंगी। श्री चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बजट में महिलाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता पर खासा जोर दिया गया है। महिला सशक्तीकरण के लिए योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जायेंगे। जहां महिलाओं को आधुनिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार किशोर को रौंदा, मौत, परिवार में मचा कोहराम

लखनऊ। पारा में साइकिल से जा रहा किशोर गिर गया, जिसके पीछे से आ रहे पिकअप ने रौंद दिया। राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना हंसखेड़ा पुलिस चौकी इलाके में 19 मंजिला भवन के पास मंगलवार को हुई। इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सूरज (15) के रूप में हुई है। वह थाना क्षेत्र अंतर्गत कांशीराम कॉलोनी, सदरौना का निवासी था। सूरज अपने दो भाइयों में छोटा था और उसकी चार बहनें भी हैं। उसके पिता छोटू विश्वकर्मा दिव्यांग हैं। मां सुनीता विश्वकर्मा जो गृहणी हैं और परचून की दुकान चलाकर परिवार का गुजारा करती हैं। मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम करा पुलिस जब शव को कांशीराम कॉलोनी पहुंची तो आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद परिजन माने और शव का अंतिम संस्कार किया।

एचडीएफसी बैंक ने लखनऊ में करेंसी चेस्ट खोला

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के विराज खंड में एचडीएफसी बैंक के नए करेंसी चेस्ट का उद्घाटन किया। यह राज्य में बैंक की चौथी और भारत में 38वीं ऐसी सुविधा होगी। इस सुविधा के साथ यहां एक पुलिस रूम, कैश रिसीट एरिया, सॉर्टिंग रूम, फायर सेफ्टी सिस्टम व वाइब्रेशन और मोशन/सेंसर के साथ-साथ एक मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर पंकज कुमार - रीजनल डायरेक्टर - रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, लखनऊ और एचडीएफसी बैंक से भावेश ज़वेरी - एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गौरव रॉय - ग्रुप हेड, डब्ल्यूबीओ ऑपरेशंस, अरुण मेदिरत्ता - ग्रुप हेड, रीजनल ब्रांच बैंकिंग, मुस्कान सिंह - ब्रांच बैंकिंग हेड (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) और बैंक के अन्य सीनियर एग्जीक्यूटिव भी मौजूद थे। करेंसी चेस्ट सभी स्टेकहोल्डर्स को सही कैश डिस्ट्रीब्यूशन और समय पर साफ़ और सही करेंसी उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। यह लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन को काफ़ी बढ़ाएगा और लखनऊ, फ़ैज़ाबाद, बाराबंकी, गोरखपुर और कानपुर ज़िलों में 246 ब्रांच, 317 एटीएम को बिना रुकावट करेंसी सप्लाई सुनिश्चित करेगा, जिससे करेंसी नोटों की उपलब्धता के लिए टर्न-अराउंड-टाइम (टीएटी) बढ़ेगा। इससे इस क्षेत्र के अलग-अलग बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन, सरकारी संस्थानों और स्थानीय निवासियों को बेहतर कैश मैनेजमेंट का फ़ायदा होगा। एचडीएफसी बैंक के एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर भावेश ज़वेरी ने कहा, एचडीएफसी बैंक बैंकिंग इकोसिस्टम की बदलती ज़रूरतों को पूरा करते हुए हर लेवल पर बैंकिंग को आसान बनाने की कोशिश करता है। लेटेस्ट करेंसी चेस्ट का लॉन्च उसी दिशा में एक और कदम है। नया चालू करेंसी चेस्ट हमें ज़्यादा तेज़ी और तेज़ी के साथ करेंसी की ज़रूरतों को पूरा करने और अपनी ऑपरेशनल पहुँच को और बढ़ाने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में बैंक का सफ़र 1997 में लखनऊ में अपनी पहली ब्रांच खोलने के साथ शुरू हुआ था। लखनऊ में 31 दिसंबर 2025 तक बैंक के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 107 ब्रांच और 198 एटीएम (सीडीएम सहित) शामिल हैं।

योगी सरकार का बजट विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की मजबूत नींव : मंत्री कपिल देव अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

● व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास बजट में 88 प्रतिशत वृद्धि, युवाओं के कौशल विकास पर बड़ा जोर

लखनऊ। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के प्रस्तुत 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट 2026-27 विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विराट संकल्प को साकार करने का मजबूत आधार है।

सरकार का यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को समर्पित है, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के बजट में वर्ष 2025-26 की तुलना में 88 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लगभग 3,349 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों में 1,90,272 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि योगी सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के 47 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए विशेष महिला शाखाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि महिलाओं के लिए 12 स्वतंत्र राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2,963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से फ़ेज-एक के अंतर्गत चयनित 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है, जबकि फ़ेज-दो के अंतर्गत 62 संस्थानों के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संचालन के लिए प्रशिक्षण व्यय के लिए एक हजार करोड़ रुपये, दस्तकार प्रशिक्षण योजना के लिए लगभग 836 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए 500 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा पिछले पांच वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कर प्रमाणित किया गया है, जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के आम बजट को बताया निराशाजनक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को पेश किये गये आम बजट को कांग्रेस पार्टी ने निराशाजनक बताया है। विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह घोर निराशाजनक, किसान, युवा एवं बेरोजगार विरोधी बजट है। बजट में बेरोजगार युवाओं को धोखा मिला है, अनुदेशकों के लिए उच्च न्यायालय ने बढ़े मानदेय और एरियर का आदेश दिया लेकिन सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में किसानों के लिए विशेष प्रबंध करेगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई और बढ़ती लागत की वजह से किसान पहले से परेशान है लेकिन इस बार भी किसानों को बजट से निराशा हुई है, हर बार डीएपी-यूरिया की किल्लत होती है उसके बाद भी सरकार ने बजट में कोई ध्यान नहीं रखा। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि आउटसोर्सिंग के लिए भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि न्यूनतम मानदेय देंगें, लेकिन बजट में कोई आवंटन नहीं, ये नौजवानों को धोखा है।

परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा की समस्त तैयारियां शासन के निर्देशानुसार पूर्ण करायें: अनुनय झा

- सतर्क एवं संवेदनशील रहकर बोर्ड परीक्षा सकुशल एवं नकल विहीन सम्पन्न करायें-डी0एम0
- परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त महिला एवं पुरूष, पुलिस की तैनाती की जायेगी- अशोक कुमार मीणा

राष्ट्रीय प्रस्तावना

हरदोई। जनपद के 133 के केन्द्रों पर 18 फरवरी से प्रारम्भ होकर 12 मार्च 2026 तक चलने वाली हाईस्कूल एवं इण्टर की बोर्ड परीक्षा 2026 को सकुशल एवं नकल विहीन सम्पन्न कराने हेतु स्थानीय रसखान प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में जोनल मजिस्ट्रेट, जोन सेक्टर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक तथा केन्द्र व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण उपस्थित केन्द्र व्यवस्थापकों को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा पुलिस परीक्षा के अनुसार ही कराई जायेगी और सभी केन्द्र व्यवस्थापक अपने केन्द्रों पर परीक्षा की समस्त तैयारियां शासन के निर्देशानुसार करायें जिसमें परीक्षार्थियों के लिए सीसी टीवी कैमरा, पेयजल, विद्युत, रैम्प, शौचालय आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के साथ विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर रखें तथा परीक्षा कक्षों मुख्य दरवाजे को छोड़कर सभी खिड़की आदि बन्द करा दें। डीएम ने कहा कि परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र पुलिस की निगरानी में निर्धारित स्थान पर पहुंचाये जायेगें तथा परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की गहन चेकिंग कराई जाये तथा के दौरान किताब, मोबाइल आदि लेकर आने वाले परीक्षार्थियों का सामान रखने के लिए एक कक्ष निर्धारित कर उसमें रखवायें। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के दौरान सेक्ट एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट पुलिस टीम के साथ निरन्तरण भ्रमणशील रहे तथा

अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान की परीक्षा के दिन विशेष सर्तकता बरते। 22 संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापकों से जिलाधिकारी ने कहा कि अपने केन्द्रों पर तटस्थ एवं सर्तक रहकर परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि जनपद में तहसील में 25, सदर में 36, शाहाबाद में 24, सण्डीला में 28 व सवायजपुर में 20 सहित कुल 133 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है जिसमें हाईस्कूल के 29756 बालक व 23277 बालिका इण्टर में 27558 बालक व 19939 बालिका कुल 100530 परीक्षार्थियों की परीक्षा कराई जायेगी। उन्होने परीक्षा में लगे अधिकारियों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों से कहा कि पूरी तरह सर्तक एवं संवेदनशील रहकर बोर्ड परीक्षा को सकुशल एवं नकल विहीन सम्पन्न करायें। प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के बाहर पर्याप्त महिला एवं पुरूष पुलिस की तैनाती की जायेगी और परीक्षा समय परीक्षा केन्द्रों के आस-पास शासन द्वारा निर्धारित दूरी तक किसी प्रकार की फोटो स्टेट, काल सेन्टर आदि की दुकाने बन्द रहेगी और परीक्षा केन्द्र के बाहर किसी भी बाहरी व्यक्ति को खड़ा नहीं होने दिया जायेगा तथा केन्द्रों के आस-पास बराबर पुलिस बल द्वारा भ्रमण किया जायेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0रा0 प्रियंका सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा केन्द्र व्यवस्थापक तथा प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम आदि उपस्थित रहें।

मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए निर्देश

राष्ट्रीय प्रस्तावना

हरपालपुर (हरदोई)। मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने बुधवार को विकास खण्ड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों में लापरवाही और वित्तीय अभिलेखों में अनियमितता मिलने पर सीडीओ ने सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेखाकार पटल पर गार्ड फाइल अद्यावधिक न पाए जाने पर लेखाकार सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करते हुए उन्हें आरोप पत्र जारी करने के निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिए।

जानकारी के अनुसार, सीडीओ ने ब्लॉक परिसर में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए इन्टरलॉकिंग कार्य की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर तकनीकी समिति से जांच कराने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में मानक की अनदेखी अक्षम्य है। इसके साथ ही सभागार की फाल्स सीलिंग सही करवाने और जर्जर पड़े बीडीओ आवास के तत्काल मूल्यांकन व निस्तारण के निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए। दफ्तरों के निरीक्षण के दौरान स्थापना, मनरेगा और एनआरएलएम सेल के अभिलेखों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं मिला। कर्मचारियों की नेमप्लेट और कार्य विवरण न होने पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने सभी पटलों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि सभी कार्मिक निर्धारित 'जॉब चार्ट' के अनुसार ही कार्य संपादित करें और शिकायत निस्तारण पंजिका को अद्यतन रखें। निरीक्षण के कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा अशोक द्विवेदी बीडीओ संजय कुमार अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

गुरुकुल में 51 बटुकों का हुआ सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, हृदयस्पर्शी दृश्य से अभिभावकों के नेत्र हुए सजल

राष्ट्रीय प्रस्तावना

कोथावाँ (हरदोई)। जनपद हरदोई से सटे नैमिषारण्य की पवित्र धरा के श्री ओम प्रकाश हनुमत संस्कृत विद्यापीठ आवासीय गुरुकुल विद्यालय में आज बुधवार को 51 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। आचार्य सुधीर मिश्रा, नीरज दिक्षित, गणेश शास्त्री, अंकित तिवारी, सचित दिक्षित आदि ने वैदिक परंपरानुसार मंत्रोच्चार के बीच बटुकों को ब्रह्मचर्य के पालन

का संकल्प दिलाया। प्रबंधक/प्रधानाचार्य अतुल मिश्रा ने बटुकों को दीक्षा और गुरुमंत्र दिया। इसके बाद बटुकों ने दोनों हाथ फैला कर परिवार वालों से भिक्षा के लिए याचना की। हृदयस्पर्शी दृश्य से अभिभावकों के नेत्र सजल हो गए।

प्रधानाचार्य ने बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत ही ब्रह्मचारी वेदाअध्ययन का अधिकारी माना जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना का पर्व ऋषियों, मुनियों, ज्ञानी जनों के लिए साधना का अमृत महोत्सव भी है। यज्ञोपवीत के तीनों सूत्र देव, ऋषि व पितृ ऋण के प्रतीक हैं। साथ ही, यह सत, रज, व तम गुणों के परिचायक भी हैं। सुबह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेई रहे। इसमें छात्रों ने संस्कृत व हिंदी काव्यानि, वसंत गीत, वैदिक मंगलाचरण, सरस्वती वंदना, स्वागत गान, नाटक आदि की प्रस्तुति दी।

इस दौरान प्रबंध समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा, विमला मिश्रा सहित नैमिषारण्य की महंत मोहिनी दास, शास्वतानानंद महाराज, विद्यानंद सरस्वती, मंडल अध्यक्ष दिग्विजय पांडेय, समाज सेवी राज वर्धन सिंह राजू, दुर्गेश मिश्रा, अरुण मिश्रा, अनुज मिश्रा, विकाश हिंदू, दिग्विजय शुक्ला सभासद, अनुराग पांडेय, महेंद्र सिंह, पंकज गुप्ता सहित सैकड़ो संत एवं बटुकों के माता-पिता मौजूद रहे।

जन सनुवाई मे सुनी 56 शिकायतें

हरदोई (राष्ट्रीय प्रस्तावना)। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई मे

कुल 56 शिकायते प्राप्त हुई, जिसके त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्व और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो। जनसुनवाई मे प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

गांव के बाहर छप्पर के नीचे सो रहे युवक की निर्मम हत्या

सण्डीला (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीतों गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर जानवरों को रखने के लिए छप्पर के नीचे सो रहे युवक को उसके परिजन जगाने गए तो देखा कि युवक के सिर में लगे गंभीर घावों से खून बह रहा था और वह मर चुका था! युवक की हत्या की खबर पूरे गांव व क्षेत्र में आग की तरह फैल गई! स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है! प्राप्त जानकारी के अनुसार संडीला थाना क्षेत्र के मीतों गांव के बाहर जानवरों को लिए बनाए गए छप्पर के नीचे सो रहे गांव के ही हुकुम सिंह (52) की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई! मृतक के पुत्र रंजीत यादव ने बताया कि जब उसका छोटा भाई अजीत सुबह पिता को जगाने गया तो उसने पिता को चारपाई पर मृत अवस्था में पाया और उनके सिर पर लगे गंभीर घावों से खून बह रहा था! घटना की जानकारी होते ही पूरे गांव में हड़कंप और परिजनों में चीख पुकार मच गई! सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकार संडीला संतोष कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक सहित पूरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची! अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि घटना का अनावरण करने के लिए फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं! शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है! घटना के प्रत्येक बिंदु की गहनता से जांच की जा रही है तथा प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है!

विवाद में महिला को बेरहमी से पीटा

हरपालपुर (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। अरवल थाना क्षेत्र के ग्राम कैथापुरवा मजरा भदार में खेत से निकलने के विवाद को लेकर एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पीड़िता मंजू देवी ने गांव के ही आशीष, तिवारीलाल और उसकी पत्नी पर लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाया है। मंजू देवी के अनुसार, जब वह खेत की ओर जा रही थीं, तब आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और विरोध करने पर मारपीट की। शोर मचने पर ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। पुलिस ने मामले की जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की कानूनी कार्रवाई जारी है।

उधार के पैसे मांगने पर दबंगो ने दुकानदार को पीटा

हरपालपुर (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। अरवल के ग्राम श्रीमऊ गांव निवासी दुकानदार अवधेश कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने गांव के ही सुधीर से अपने पैसे मांगे, तो सुधीर ने अपने साथियों जतन, सत्यम, दीपक और अश्वनी सहित 6 अन्य लोगों के साथ उनकी दुकान पर हमला कर दिया। आरोपियों ने अवधेश और उनके बेटे सूरज की लाठी-डंडों से पिटाई की और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। अरवल पुलिस ने इस मामले में सुधीर और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अज्ञात वाहन की टककर से युवक की मौत

शाहाबाद (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। कोतवाली छेत्र के ग्राम नगला कल्लू के निकट मंगलवार की रात ग्यारह बजे करीब सड़क पर टहल रहे युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु हो गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हरदोई भेजा है। प्राप्त विवरण में ग्राम नगला कल्लू निवासी बबलू पुत्र राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के सभी घरवाले मांगलवार की रात विवाह समारोह में गए थे। नींद न आने की वजह से बबलू गांव के बाहर सड़क पर टहलने निकला था। रात करीब ग्यारह बजे किसी अज्ञात वाहन के चालक ने उसके टककर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हरदोई भिजवाया है।

किशोरी लापता, आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज

शाहाबाद (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी के लापता होने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित पिता के अनुसार उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बुधवार की सुबह करीब 4 बजे कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिकंदर पुर कल्लू निवासी कुलदीप पुत्र रामकुमार उर्फ़ कल्लू अपने रिश्तेदार दीपू गणेश पुत्रगण गुलाब उर्फ़ शंकर लाल के सहयोग से बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुत्री घर में रखे पंद्रह हज़ार रूपए नगद और एक लाख रूपए के ज़ेवर अपने साथ लेकर गयी है। पुत्री को काफ़ी तलाश किया। लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पिता की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

शांति व सौहार्द को लेकर कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक

पीस कमेटी की बैठक करते प्रभारी निरीक्षक अमित — फोटो: राष्ट्रीय प्रस्तावना

राष्ट्रीय प्रस्तावना

कछौना (हरदोई)। कोतवाली परिसर में बुधवार को आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई! बैठक की अध्यक्षता प्रभारी निरीक्षक ने की! बैठक में सभी समुदायों से संभ्रांत लोग, जनप्रतिनिधि, व्यापारी बंधुओं ने भाग लिया! बैठक के दौरान आगामी त्यौहारों जैसे शिवरात्रि होली व ईद को शांति व सौहार्द पूर्ण वातावरण में मनाने पर विशेष रूप से चर्चा हुई! पुलिस प्रशासन ने उपस्थित लोगों से भाईचारा बनाए रखने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की! प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि आपसी भाईचारा व सौहार्द बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है! किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दें! उन्होंने त्रिनेत्र एप में सहयोग करने हेतु आए हुए लोगों से अपने घरों पर सीसीटीवी लगाने की भी अपील की! बैठक में उपस्थित लोगों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया!

बैठक में उपस्थित सभी ने क्षेत्र में अमन चैन और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया!

बंदर से टकराकर फिसली बाइक, तीन घायल

शाहाबाद (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिकंदर पुर कल्लू के निकट बुधवार की सुबह करीब ग्यारह बजे सड़क पर अचानक बंदर आ जाने से बाइक फिसल कर पलटने में दो बुजुर्ग सहित तीन लोग घायल हुए हैं जिसमे दो लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए से हायर सेंटर रेफर किया गया है। लखीमपुर खीरी जनपद के मैगलगंज कस्बा के मोहल्ला बाकुआँ निवासी घायल संजय के अनुसार वह अपने परिवार के बड़े भाई 70 वर्षीय देवकीनंदन और भाभी 68 वर्षीय सरोजनी देवी को बाइक से लेकर पाली कस्बे में एक रिश्तेदार के यहां तेरहवीं में जा रहे थे। सिकंदर पुर कल्लू के थोड़ा पहले अचानक एक बंदर सड़क पर आ गया और बाइक में फंस गया जिससे बाइक सड़क पर फिसल गई और तीनों घायल हो गए। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस से उन्हें सीएचसी शाहाबाद भिजवाया। डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद देवकीनंदन और सरोजनी देवी को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है।

ई-रिक्शा पलटने से पाँच लोग हुए घायल

हरपालपुर (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। अरवल के शेखपुर गांव के समीप पलिया-चौंसार मार्ग पर बुधवार को एक अनियंत्रित ई.रिक्शा पलटने से उसमें सवार पांच लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब चालक सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहा था। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, हरपालपुर के सिरसा निवासी सुशीला अपनी पुत्री शिवानी और बहन नीतू के साथ कन्नौज से वापस अपने मायके बरसोहिया गांव जा रही थीं। ई-रिक्शा पर सवार होकर जाते समय अचानक मार्ग पर शेखपुर गांव निवासी मोनू पुत्र राहुल को बचाने के फेर में चालक नियंत्रण खो बैठा और ई-रिक्शा बीच सड़क पर पलट गया। हादसे में रिक्शा शेखापुरा निवासी सुबोध भी चोटिल हुए हैं। मौके पर राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ई-रिक्शे के नीचे दबे घायलों को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सुशीला की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।

केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वाहन पर होने जा रही आम हड़ताल

राष्ट्रीय प्रस्तावना

हरदोई। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वाहन पर शुक्रवार को होने जा रही आम हड़ताल में 25 से 30 करोड़ कामगार शामिल हो रहे हैं। यह हड़ताल कार्रवाई एक बहुत ही नाजुक स्थिति में हो रही है, जब केंद्र सरकार, ट्रेड यूनियनों को नियंत्रित करने और कमजोर करने और भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन को पूंजी के हमले के सामने निहत्था करने के लिए, चार श्रम संहिताएं और उसके बाद नियम अधिसूचित किए हैं।

इस हड़ताल में बैंक कर्मियों के 3 संगठन आल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन, आल इंडिया बैंक आफीसर्स एसोसिएशन और बैंक इम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया शामिल हो रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अन्य घटक संगठनों में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े नेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक आफीसर्स को छोड़कर, का नैतिक भ्रातत्व समर्थन है। आल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन के राज्य संगठन यूपी बैंक इम्प्लाइज यूनियन की स्थानीय इकाई के सेक्रेटरी राकेश पाण्डेय के नेतृत्व में गुरुवार शाम को कार्यदिवस की समाप्ति पर शहर की बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य शाखा पर बैंक कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिसमें विभिन्न बैंको के कर्मचारी शामिल हुए। यूनियन की महिला संयोजिका श्रीमती प्रिया रस्तोगी ने कहा कि मज़दूर विरोधी श्रम संहिताएँ वापस लो मज़दूर वर्ग पर हमले बंद करो युवाओं के रोज़गार पर हमले रोको। पीएनबी से अजय मेहरोत्रा ने कहा कि बैंकों, बीमा और सामान्य बीमा में निजीकरण एवं विनिवेश बंद करो। आईडीबीआई बैंक को बेचने का निर्णय वापस लो। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनिल कुमार ने कहा कि बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई वृद्धि वापस लो। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को एक इकाई में विलय करो। यूनियन बैंक के कौशलेंद्र शुक्ला ने कहा कि पर्याप्त भर्तियाँ सुनिश्चित करो, युवाओं को स्थायी रोज़गार दो। आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा बंद करो, मज़दूरों का शोषण रोको। बैंक ऑफ इंडिया के आनंद वर्मा ने कहा कि नई पेंशन स्कीम खत्म करो- पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करो। सेंट्रल बैंक की वर्षा मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट्स से बकाया डूबे कर्ज़ की वसूली के लिए कड़े कदम उठाये। आम ग्राहकों के लिए बैंकों में सेवा शुल्क कम करे। प्रदर्शनकारियों में आशुतोष बडोला, संतोष कुमार, पूजा सिंह, राम मिलन, चंद्र शेखर, अमित शर्मा, नीतीश, विवेक, विभांशु, अमित पाण्डेय, संदीप शामिल रहे।

वर्ष में एक बार पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन करायें: जिलाधिकारी

राष्ट्रीय प्रस्तावना

हरदोई। जिला पुस्तकालय समिति की बैठक आज जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानन्द सभागार कलेक्ट्रेट में आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा पुस्तकालय पंजीकरण सदस्यता शुल्क 500/रू0 और प्रत्येक वर्ष 240/रू0 सदस्यता शुल्क निर्धारित किया जाये तथा समय पर सदस्यता शुल्क जमा कराया जाये। समिति में पेंशनर्स व महिला मंगल दल सदस्य नियुक्ति के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी की अध्यक्षता में योग्य सदस्यों को नामित करायें तथा पुस्तकों को ऑनलाइन कराने के साथ मिशन अभ्योदय योजना के तहत छात्र-छात्राओं का सेशन करायें और वर्ष में एक बार पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन करायें एवं सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलायें तथा पुस्तकालय में सदस्यों आदि के सभी सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये। इस अवसर पर पीडी, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम आदि उपस्थित रहे।

पैदल जा रहे विकलांग व्यक्ति की कंटेनर से कुचलकर मौत

पिहानी (हरदोई)(राष्ट्रीय प्रस्तावना)। विकास खंड पिहानी से जहानीखेड़ा रोड पंडरवा किला स्थित आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के सामने पैदल जा रहे एक विकलांग व्यक्ति को अज्ञात कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति शादी का बुलावा देने घर से निकले थे। हादसे के बाद कंटेनर चालक वाहन समेत पिहानी की तरफ फरार हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाल मौके पर पहुंचे तथा हल्का इंचार्ज राजेश सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और अज्ञात कंटेनर की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक व्यक्ति विकलांग थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। वे शादी का बुलावा देने के लिए घर से निकले थे लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जान चली गई। इस हादसे से परिवार में कोहराम मचा है और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात कंटेनर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत-बेहटा मुर्तजाबक्श, विकास खण्ड-अहिरोरी, जनपद-हरदोई

पत्रांक- मेमो/मनरेगा/2025-26 दिनाँक-11.02.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

कार्यालय ग्राम पंचायत-बेहटा मुर्तजाबक्श, विकास खण्ड-अहिरोरी, जनपद- हरदोई द्वारा मनरेगा से कराए जाने वाले निम्नलिखित कार्यो की सामग्री (सीमेण्ट, मौरंग, बालू, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट, रोड़ा, ईट प्रथम आदि) आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्मो से निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदायें दिनाँक-12.02.2026 से 14.02.2026 को 03:00 बजे तक प्राप्त कर जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाएं दिनाँक-14.02.2026 को समिति द्वारा सायं 04:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी।

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	मेवा के मकान से पुलिया तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	992576.00

नोट- नियम व शर्ते निम्नवत् है-

1- निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त हुयी किसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2- निविदा फार्म पर किसी प्रकार की कटिंग मान्य नही होगी।
3- बिना बताये किसी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
4- निविदा फार्म पर उल्लेखित साफ शब्दों में अंकित करें।
5- धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।
6- कार्यो की कटौती प्रावधान/ लागू दरों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
7- प्राविधारित कार्यो / सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
8- समस्त सामग्री की आपूर्ति कार्य स्थल पर की जाएगी।

(मिही लाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत- बेहटा मुर्तजाबक्श,
विकास खण्ड- अहिरोरी, हरदोई

(उज्जवल यादव)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत- बेहटा मुर्तजाबक्श,
विकास खण्ड- अहिरोरी, हरदोई

नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ता भारत

शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ (2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घृणास्पद बयान यानी हेट स्पीच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को स्वतरू संज्ञान लेकर शिकायत का इंतजार किए बिना अपराधियों के खिलाफ तत्कालीन आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी, 295 ए और 505 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी निष्क्रियता या हिचकिचाहट कर्तव्य की गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा शीर्ष अदालत के इस निर्देश से भी परे हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए ली गई संवैधानिक शपथ की तो धज्जियां वो सांप्रदायिक जहर उगलते हुए लगातार उड़ा ही रहे हैं, अब वो अदालती निर्देश की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। क्या हिमंता बिस्वासरमा गुजरात मॉडल के कारण निश्चिंत हैं, जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा का जानलेवा माहौल बना, लेकिन सत्ता पर बैठे लोगों का बाल भी बांका नहीं हुआ। बल्कि आगे उन्हें पदोन्नत कर शिखर पर बिठा दिया गया। 2002 में गुजरात के कारण सवाल उठने लगा था कि क्या हम नाजी जर्मनी के दौर में पहुंच रहे हैं, लेकिन तब ये सवाल एक राज्य तक ही सीमित था। अब इसका दायरा बढ़ते हुए राष्ट्रव्यापी हो चुका है। इक्का-दुक्का राज्यों को छोड़कर हर जगह सांप्रदायिक नफरत घुन की तरह व्यवस्था के भीतर पैठ जमा चुकी है। लगभग रोजाना ऐसी खबरें आती हैं, जहां केवल धर्म के नाम पर किसी नागरिक या नागरिकों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अभी असम से जो खबरें आई हैं, वो बेहद चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी की असम ईकाई ने अपने आधिकारिक श्एक्स्य अकाउंट से 7 फरवरी को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसे एक दिन बाद ही हटा दिया गया लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर यह उपलब्ध है। वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वासरमा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वे मुसलमान दिख रहे लोगों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें गोली मार रहे हैं। इस विवादित वीडियो में इस्तेमाल की गई तस्वीरों और श्पॉइंट ब्लैंक शॉटश और श्कोई दया नहींश जैसे बयान भी हैं, जो सीधे-सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाले हैं। इस वीडियो पर कांग्रेस, शिवसेना, राजद, एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दल तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन असल में कार्रवाई की ताकत जिनके पास है, उनकी चुप्पी बेहद डरावनी लग रही है। डर लग रहा है कि असम में अभी किए जा रहे इस प्रयोग को अगर बाकी देश पर भी किया गया तो क्या होगा। केंद्र सरकार यानी नरेन्द्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि वे इस बारे में या हिमंता बिस्वासरमा के खिलाफ कुछ कहेंगे। क्योंकि यह सब उनकी ही शह पर हो रहा होगा, अन्यथा कोई भाजपाई मुख्यमंत्री इतना दुस्साहस नहीं दिखा सकता। राष्ट्रपति महोदया भी केवल दही-चीनी खिलाने को ही अपना काम मान बैठी हैं। जब वे मणिपुर पर चुप रहीं तो असम पर भी चुप रहेंगी। चुनाव आयोग से भी कोई उम्मीद रखना बेमानी है। जब 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम ज्यादा बच्चों वाला तंज मुसलमानों पर कस रहे थे, या झारखंड चुनाव में घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे थे, आयोग तब भी सब देखता रहा और अब भी वह कुछ नहीं कहेगा। ले देकर उम्मीद बचती है सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन इन पंक्तियों के लिखे जाने तक वहां भी खामोशी ही है। आश्चर्य है कि माननीय न्यायालय को 2022 का दिया गया अपना ही निर्देश याद क्यों नहीं है। अगर इस मामले में अदालत की तरफ से कार्रवाई के निर्देश आते हैं, तब तो देश, संविधान, लोकतंत्र के बचे रहने की उम्मीद भी बचेगी, वर्ना विपक्ष अपनी तरफ से इन्हें जिंदा रखने की जो लड़ाई लड़ रहा है, बस वही आसरा अब रह गया है। ऐसा नहीं है कि हिमंता बिस्वा सरमा ने संवैधानिक पद पर होने के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पहली बार जहर उगला है, वे तो लगातार इस नफरत को बढ़ाते ही जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले डिगबोई में उन्होंने कहा था कि श्मियां मुसलमानों को किसी भी तरीके से परेशान करो। अगर वे परेशानी का सामना करेंगे, तो वे असम से चले जाएंगे।

मुख्यमंत्री पद के लिए ली गई संवैधानिक शपथ की तो धज्जियां वो सांप्रदायिक जहर उगलते हुए लगातार उड़ा ही रहे हैं, अब वो अदालती निर्देश की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। क्या हिमंता बिस्वासरमा गुजरात मॉडल के कारण निश्चिंत हैं, जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा का जानलेवा माहौल बना, लेकिन सत्ता पर बैठे लोगों का बाल भी बांका नहीं हुआ। बल्कि आगे उन्हें पदोन्नत कर शिखर पर बिठा दिया गया। 2002 में गुजरात के कारण सवाल उठने लगा था कि क्या हम नाजी जर्मनी के दौर में पहुंच रहे हैं, लेकिन तब ये सवाल एक राज्य तक ही सीमित था।

क्यों गायब हो रहे बच्चे?

डॉ. प्रियंका सौरभ

हरियाणा में भिक्षावृत्ति और बालश्रम से मुक्त कराए गए 350 से अधिक बच्चों के मामले इस सच्चाई को और उजागर करते हैं। चौक-चौराहों, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों पर दिखाई देने वाले ये बच्चे किसी संयोग का परिणाम नहीं हैं। ये एक सुनियोजित तंत्र के तहत यहां लाए जाते हैं, जहां उनसे काम कराया जाता है या उन्हें भिक्षावृत्ति में धकेला जाता है। इनसे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा गिरोह या प्लेसमेंट एजेंसियों के पास चला जाता है, जबकि बच्चों को अमानवीय परिस्थितियों में जीने को मजबूर किया जाता है। यह भी गौर करने योग्य है कि मानव तस्करी अब अकेला अपराध नहीं रहा। पुलिस और जांच एजेंसियों का मानना है कि नशा तस्करी, साइबर अपराध, एक्सटॉर्शन और मानव तस्करी जैसे अपराध अब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही नेटवर्क कई तरह के अवैध कामों को अंजाम दे रहा है।

हरियाणा में गुमशुदगी के बढ़ते मामले अब केवल पुलिस रजिस्टरों या अख़बारों की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहे हैं। ये मामले उन हजारों परिवारों की अनकही पीड़ा हैं, जिनके घरों से कोई सदस्य काम, पढ़ाई या रोज़मर्रा के काम के लिए निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। हर दिन औसतन 12 बच्चों का लापता होना और वर्ष 2025 में 17,500 से अधिक गुमशुदगी के मुकदमों का दर्ज होना, किसी भी संवेदनशील समाज के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए। यह स्थिति न सिर्फ कानून-व्यवस्था की चुनौती है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। गुमशुदगी का सबसे भयावह पहलू यह है कि इसके पीछे अब केवल व्यक्तिगत विवाद, घरेलू कारण या आकस्मिक घटनाएं नहीं रहीं। जांच में बार-बार यह संकेत मिल रहे हैं कि कई मामलों की जड़ें मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों से जुड़ी हुई हैं। पुलिस के अनुसार करीब 75 प्रतिशत मामलों को ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन शेष 25 प्रतिशत अधूरे मामले ही असली चिंता का कारण हैं। यही वे मामले हैं जिनमें लापता व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिलता और जिनके पीछे अंतरराज्यीय गिरोह, अवैध प्लेसमेंट एजेंसियां और आर्थिक शोषण के नेटवर्क काम कर रहे होते हैं। विशेष चिंता इस बात की है कि महिलाएं और नाबालिग बच्चे इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं। बेहतर रोजगार, उज्ज्वल भविष्य या शिक्षा का सपना दिखाकर बच्चों और युवाओं को उनके घरों से दूर ले जाया जाता है। कई बार माता-पिता खुद मजबूरी में बच्चों को ऐसे एजेंटों के हवाले कर देते हैं, जिन्हें वे भरोसेमंद समझते हैं। बाद में वही भरोसा परिवारों के लिए जीवनभर का पछतावा बन जाता है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों से जुड़े नेटवर्क इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह समस्या स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर फैले संगठित अपराध का हिस्सा है। हरियाणा में भिक्षावृत्ति और बालश्रम से मुक्त कराए गए 350 से अधिक बच्चों के मामले इस सच्चाई को और उजागर करते हैं। चौक-चौराहों, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों पर दिखाई देने वाले ये बच्चे किसी संयोग का परिणाम नहीं हैं। ये एक सुनियोजित तंत्र के तहत यहां लाए जाते हैं, जहां उनसे काम कराया जाता है या उन्हें भिक्षावृत्ति में धकेला जाता है। इनसे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा गिरोह या प्लेसमेंट एजेंसियों के पास चला जाता है, जबकि बच्चों को अमानवीय परिस्थितियों में जीने को मजबूर किया जाता है। यह भी गौर करने योग्य है कि मानव तस्करी अब अकेला अपराध नहीं रहा। पुलिस और जांच एजेंसियों का मानना है कि नशा तस्करी, साइबर अपराध, एक्सटॉर्शन और मानव तस्करी जैसे अपराध अब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही नेटवर्क कई तरह के अवैध कामों को अंजाम दे रहा है। यही कारण है कि गुमशुदगी के मामलों की जांच अब संगठित अपराध के नजरिये से की जा रही है। यह बदलाव सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसके लिए संसाधनों, तकनीक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी उतनी ही जरूरत है। हरियाणा पुलिस द्वारा वर्ष 2026 के लिए तैयार किया गया अपराध नियंत्रण रोडमैप उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाता है। संगठित अपराधियों पर कड़ी निगरानी, तकनीक के माध्यम से पहचान और ट्रैकिंग, अंतरराज्यीय समन्वय और समयबद्ध जांच जैसे कदम निस्संदेह आवश्यक हैं। पुलिस महानिदेशक का यह स्पष्ट संदेश कि बच्चों और महिलाओं से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भरोसा पैदा करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल प्रशासनिक सख्ती से इस गहरी समस्या को पूरी तरह सुलझाया जा सकता है? सच्चाई यह है कि गुमशुदगी और मानव तस्करी जैसी समस्याएं केवल कानून-व्यवस्था के दायरे में सुलझने वाली नहीं हैं। इनके पीछे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे कारण भी काम करते हैं। जब परिवारों के पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं और बेहतर जीवन का सपना उन्हें हर दिन बेचैन करता है, तब वे अक्सर गलत हाथों में फंस जाते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि उन परिस्थितियों को बदलने की भी होनी चाहिए, जो लोगों को असुरक्षित बनाती हैं। समाज की भूमिका यहां सबसे अहम हो जाती है। अक्सर लोग लापता बच्चों या संदिग्ध गतिविधियों को देखकर भी चुप रह जाते हैं। यह किसी और का मामला है जैसी सोच अपराधियों के हौसले बढ़ाती है। यदि समय रहते संदिग्ध प्लेसमेंट एजेंसियों की सूचना दी जाए, भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को नजरअंदाज न किया जाए और लापता होने की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जाए, तो कई मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। जागरूक समाज ही किसी भी अपराध के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकता है। बाल अधिकार विशेषज्ञों का यह कहना बिल्कुल सही है कि बच्चों को तस्करी से मुक्त कराना केवल पहला कदम है। असली चुनौती उनके पुनर्वास, शिक्षा और मानसिक काउंसलिंग की है। तस्करी का शिकार हुए बच्चे गहरे मानसिक आघात से गुजरते हैं। यदि उन्हें समय पर सही देखभाल और अवसर नहीं मिले, तो वे दोबारा उसी अंधेरे चक्र में फंस सकते हैं। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सम्मानजनक हो। हरियाणा में गुमशुदगी के मामले हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास और आर्थिक प्रगति के दावों के बीच कहीं हम मानवीय मूल्यों को तो नहीं खोते जा रहे। यह समस्या केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हर उस परिवार की कहानी है, जो आज भी किसी दरवाजे की आहट पर उम्मीद लगाए बैठा है। यदि अब भी इसे केवल एक खबर या एक प्रशासनिक चुनौती समझकर नजरअंदाज किया गया, तो आने वाले वर्षों में इसकी कीमत कहीं ज्यादा भारी होगी। समय की मांग है कि गुमशुदगी को अपराध के साथ-साथ मानवीय संकट के रूप में देखा जाए। सरकार, पुलिस, समाज और नागरिक—सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई बच्चा, कोई महिला या कोई नागरिक यूं ही गुम न हो जाए और उसका परिवार जिंदगी भर इंतजार करने को मजबूर न रहे।

ओटीटी की भाषा, हिन्दी और हम

डा. अवधेश कुमार यादव

ओटीटी पर अश्लील कंटेंट की बाढ़ से न केवल संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है, बल्कि समाज में भाषा की गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो रही है। रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी के नाम पर अश्लील सीन और संवाद आम हो गए हैं, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में हर व्यक्ति हर वाक्य में गाली देता है? क्या कॉलेज के छात्रों की सामान्य भाषा इतनी गंदी होती है? यह सब युवा पीढ़ी पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रहा है।

चण्डीगढ़ के गुप्ता जी रविवार के दिन मनोरंजन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी वेब सीरीज देख रहे थे। उनका पांच साल का बेटा मोबाइल गेम में व्यस्त था। तभी टेलीविजन स्क्रीन पर पात्र अचानक से एक-दूसरे को जोर-जोर से गालियां देने लगे, जिसे देखकर उनका बेटा भी जोर-जोर से दोहराने लगा। गुप्ता जी रिमोट से सीरीज बंद कर देते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यह क्या हो रहा है? बचपन में तो हम अखबार पढ़कर भाषा सीखते थे। संपादकीय पन्नों से नए शब्द, मुहावरे और व्याकरण की बारीकियां आत्मसात करते थे। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बच्चों की जुबान गंदी कर रहे हैं। हिंदी न्यूज चैनल तो हिंग्लिश में ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से पढ़े पत्रकार 'ग्राउंड जीरो' और 'एक्सक्लूसिव' जैसे शब्द हिंदी में लिखकर प्रसारित कर देते हैं। ओटीटी ने 'रियलिज्म' के नाम पर अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं। एक समय था जब हिंदी भाषा की शुद्धता, व्याकरण और वर्तनी का सबसे बड़ा शिक्षक अखबार हुआ करता था। 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी के अधिकांश भाग तक अखबार घर-घर में भाषा सिखाते थे। लोग संपादकीय, लेख और समाचार पढ़कर नए शब्द सीखते, मुहावरे समझते और व्याकरण की बारीकियां आत्मसात करते। हिंदी की लयबद्धता, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली और उर्दू की मिठास का सुंदर संयोजन अखबारों की भाषा में झलकता था। वह दौर था जब भाषा को सम्मान दिया जाता था और उसे सँवारने का सतत प्रयास होता था। फिर, टेलीविजन का दौर आया। 1980-90 के दशक में दूरदर्शन पर सरकारी नियंत्रण के कारण भाषा काफी हद तक शुद्ध बनी रही, लेकिन निजी न्यूज चैनलों के उदय के साथ सब कुछ बदल गया। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ने नई पीढ़ी को हिंदी से दूर कर दिया। स्कूलों में अंग्रेजी को प्रधानता मिली, हिंदी को माध्यमिक भाषा का दर्जा दिया जाने लगा। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े-लिखे युवा जब हिंदी न्यूज चैनलों में पत्रकार बने, तो उन्होंने हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों को जबरदस्ती घुसेड़ना शुरू कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड जीरो, एक्सक्लूसिव, स्पॉटलाइट, सोर्सेज के मुताबिक, डेवलपमेंट्स हो रही है जैसे वाक्य आम हो गए। ब्रेकिंग न्यूज की होड़ में अनुवाद की जल्दबाजी ने व्याकरण और शुद्धता को ताक पर रख दिया। चैनलों पर चीख-चीखकर खबरें पढ़ी जाने लगीं, जिससे भाषा की मर्यादा भी कमजोर पड़ गई। लेकिन असली तबाही ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म्स के साथ आयी। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज़्नी प्लस, हॉटस्टार, ज़ी फाइव आदि पर हिंदी वेब सीरीज ने भाषा की सारी पारंपरिक सीमाएं तोड़ दीं। संवाद अब शुद्ध हिंदी में नहीं, बल्कि हिंग्लिश, क्षेत्रीय बोलियों के मिश्रण और सबसे ज्यादा गालियों से भरे होते हैं। मिर्ज़ापुर, सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक, कॉलेज रोमांस, हॉस्टल डेज़ जैसी वेब सीरीज में हर दूसरे वाक्य में अश्लील शब्द सुनाई देते हैं। ये शब्द अब सिर्फ पात्रों की भाषा नहीं रहे, बल्कि युवाओं की रोजमर्रा की जुबान बनते जा रहे हैं। ओटीटी पर अश्लील कंटेंट की बाढ़ से न केवल संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है, बल्कि समाज में भाषा की गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो रही है। रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी के नाम पर अश्लील सीन और संवाद आम हो गए हैं, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में हर व्यक्ति हर वाक्य में गाली देता है? क्या कॉलेज के छात्रों की सामान्य भाषा इतनी गंदी होती है? यह सब युवा पीढ़ी पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रहा है। बच्चे और किशोर इन शब्दों को सुन-देखकर अपनी भाषा में शामिल कर लेते हैं, जिससे समाज में गाली-गलौज सामान्य लगने लगी है। 2025 में स्थिति और गंभीर हुई तो सरकार ने अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाए। जुलाई 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (जिनमें उल्लू, एएलटीटी, बिग शॉट्स, डेसिफ्लिक्स, नियॉनएक्स वीआईपी इत्यादि) को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये अश्लील, वल्गर और पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित कर रहे थे। यह कार्रवाई आईटी एक्ट, 2000 और 2021 के इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत की गई। इससे पहले 2024 में भी 18 प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। कुल मिलाकर, जुलाई 2025 तक 43 प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हो चुके हैं। सरकार ने 2024 के अंत से ही ओटीटी कंटेंट के लिए नए दिशा-निर्देशों पर काम शुरू किया था, जिसमें प्रोफ़ेनिटी (गाली-गलौज) को बीप करना, अश्लील सीन को ब्लर करना और इंटीमेट सीन के वैकल्पिक चित्रण को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि मुख्यधारा के प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम आदि पर अभी भी सेंसरशिप नहीं है, बल्कि सेल्फ-रेगुलेशन और आईटी रूल्स 2021 के तहत तीन-स्तरीय तंत्र है। दिसंबर 2025 में सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि ओटीटी कंटेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के दायरे में नहीं आता, बल्कि अलग से आईटी रूल्स के तहत नियंत्रित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है कि प्रोफ़ेनिटी अपने आप में ओब्सेनिटी नहीं है (जैसे कॉलेज रोमांस मामले में 2024 का फैसला), लेकिन अश्लीलता और बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। अप्रैल 2025 में कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया को नोटिस जारी किया था। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति और समाज का दर्पण है। जब भाषा में गंदगी आएगी, तो समाज में भी वह फैलेगी। युवा पीढ़ी की जुबान खराब हो रही है। अखबारों ने हिंदी को ऊंचा उठाया, टीवी ने गिराया और ओटीटी ने इसे गटर तक पहुंचा दिया। अब समय आ गया है कि सेन्सरशिप या सख्त रेगुलेशन को जरूरी माना जाए। सरकार को चाहिए कि मुख्यधारा ओटीटी पर भी प्रोफ़ेनिटी फिल्टर, आयु-आधारित सख्त क्लासिफिकेशन और ब्लरिंग जैसे उपाय अनिवार्य करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा, सांस्कृतिक गरिमा और भाषा की पवित्रता इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओटीटी ने मनोरंजन के नाम पर भाषा और संस्कृति को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब हमें तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अखबारों की शुद्ध हिंदी सीखे या ओटीटी की गालियों से भरी जुबान अपनाए। सेन्सरशिप नहीं तो कम से कम सख्त रेगुलेशन जरूरी है, वरना हिंदी की दुर्गति रुकने का नाम नहीं लेगी।

लोकसभा-अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वासः लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा

ललित गर्ग

**लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह सदन की गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा और सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यदि विपक्ष का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि अध्यक्ष का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या उनकी आवाज को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि संस्थागत अविश्वास का संकेत होता है। 100 से अधिक सांसदों द्वारा हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी यह दर्शाती है कि मामला क्षणिक आक्रोश का नहीं, बल्कि लंबे समय से पनप रही असहमति और संवादहीनता का परिणाम है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक की भूमिका में होते हैं, जिनके प्रति विश्वास जरूरी होता है और उनसे भी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि संख्या बल के आधार पर इस तरह का प्रस्ताव पारित होना कठिन है, लेकिन लोकतंत्र में कई बार प्रतीकात्मक कदम भी गहरे संदेश देते हैं। विपक्षी दलों द्वारा यह स्पष्ट करना कि वे टकराव के साथ-साथ सुलह का विकल्प भी खुला रखे हुए हैं, और इसी क्रम में विभिन्न वरिष्ठ नेताओं का अध्यक्ष से मुलाकात कर संवाद का प्रयास करना, इस बात का संकेत है कि अभी भी समाधान की गुंजाइश समाप्त नहीं हुई है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर संवाद की जगह हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध क्यों हावी होता जा रहा है। क्या यह केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास का परिणाम है, या फिर संसदीय परंपराओं के क्षरण का संकेत? विगत वर्षों में बार-बार यह देखने को मिला है कि महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। इससे न केवल विधायी कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। इसके लिए सदन में बोलने का अवसर, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान अनिवार्य है। यदि विपक्ष यह महसूस करता है कि उसके लिए ये रास्ते संकुचित किए जा रहे हैं, तो उसका आक्रोश सड़कों या नारेबाजी के रूप में फूट पड़ता है, जो अंततः संसद की गरिमा को ही नुकसान पहुँचाता है। दूसरी ओर, विपक्ष द्वारा बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करना भी उतना ही गंभीर दोष है, क्योंकि इससे शासन की प्रक्रिया ठप होती है और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस दोतरफा अविश्वास और आक्रामकता के बीच लोकतंत्र का मूल उद्देश्य कहीं खोता हुआ दिखता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि संसद बार-बार हंगामे, निलंबन और गतिरोध की खबरों में रहे, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावित करता है। विकास, नीति और जनकल्याण की चर्चा के स्थान पर यदि टकराव और अविश्वास केंद्र में आ जाए, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत सरकार से नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष संस्थानों से भी आती है। लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल नियमों का पालन कराए, बल्कि विश्वास का सेतु भी बने। वहीं विपक्ष से भी यह अपेक्षा है कि वह विरोध को रचनात्मक बनाए, न कि अवरोध का माध्यम। आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद को फिर से संवाद का मंच बनाया जाए, जहाँ तीखी असहमति भी मर्यादा में व्यक्त हो और सत्ता व विपक्ष दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएँ। अविश्वास प्रस्ताव जैसे कदम यदि चेतावनी के रूप में लिए जा रहे हैं, तो उन्हें आत्ममंथन का अवसर भी बनना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि लोकतंत्र की संस्था को कैसे स्वस्थ, विश्वसनीय और प्रभावी बनाया जाए। जनता ने सांसदों को नारे लगाने या कार्यवाही बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर गंभीर विमर्श के लिए चुना है। यदि संसद इस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। यह भी तथ्य है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला का संसदीय संचालन अब तक सामान्यतः अनुशासित, कार्यकुशल और नियमसम्मत माना जाता रहा है। उनके कार्यकाल में लोकसभा की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को प्राथमिकता देने और विभिन्न दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनेक अवसरों पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है तथा संसदीय परंपराओं और नियमों के पालन पर बल दिया है। उनकी छवि एक ऐसे अध्यक्ष की रही है जो सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए होशियारी, धैर्य और व्यावहारिक समझ का प्रयोग करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संसदीय मर्यादाओं का आग्रह और संवाद के लिए दरवाज़े खुले रखने की प्रवृत्ति को देखते हुए उनके जैसे लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति अपने आप में एक त्रासद और चिंताजनक घटना प्रतीत होती है। यह घटना व्यक्ति विशेष से अधिक उस माहौल की ओर संकेत करती है, जहाँ अविश्वास इतना गहरा हो चुका है कि संवाद और विश्वास के पुल कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अंततः यह समय आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकार करने का है। सत्तापक्ष को यह समझना होगा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि विरोध की भी एक मर्यादा और रचनात्मकता होती है। और अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों को यह स्मरण रखना होगा कि उनकी निष्पक्षता केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि व्यवहार और अवसर की समानता से भी सिद्ध होती है। यदि संसद को संवाद का मंच बनाए रखने में हम विफल रहते हैं, तो यह केवल एक सत्र या एक सरकार की विफलता नहीं होगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक असफलता मानी जाएगी। यही वह बिंदु है जहाँ हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि और हर संस्था को आत्मचिंतन करना होगा, ताकि विकास की राह में विनाश की संभावनाएँ नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और लोकतांत्रिक परिपक्वता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

पौधारोपण अभियान की तैयारी में डीएम ने दिए समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

कौशाम्बी। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में उदयन सभागार में जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पौधारोपण अभियान-2026 की तैयारियों एवं पूर्व में रोपित पौधों की जीवितता की समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पौधारोपण अभियान-2025 के अंतर्गत लगाये गये पौधों की जीवितता की समीक्षा करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित किया कि रोपित 50 स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामों में नियमित रूप से ल्लग्रीन चौपालङ्क का आयोजन कराया जाए

तथा प्रत्येक ब्लॉक में विकसित किए गए विशिष्ट वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाय। जिला गंगा समिति के सदस्य विनय पण्डा के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी, दारानगर को कुबरी घाट पर साफ-सफाई, शेड, शौचालय, पेयजल एवं डस्टबिन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी को सिविल सोसाइटी एवं युवाओं की सहभागिता से वृहद स्तर पर गंगा स्वच्छता अभियान संचालित करने के निर्देश भी दिये।

जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग को कुबरी घाट एवं कलेश्वर घाट को जोड़ने हेतु 10 दिन के भीतर डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इस दौरान प्रभागीय वनाधिकारी ने अवगत कराया कि पौधारोपण अभियान-2026 के अंतर्गत जनपद को 39 लाख 73 हजार 100 पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने तथा अभियान में नवाचार अपनाने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने खाद एवं रसद विभाग की समीक्षा के दौरान रिक्त उचित दर दुकानों पर शीघ्र नियुक्ति के दिए आदेश

कौशाम्बी। डॉ. अमित पाल ने उदयन सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभागीय योजनाओं एवं लंबित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में रिक्त चल रही 03 उचित दर दुकानों पर नियमानुसार समयबद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुकान रिक्त होने की स्थिति में विलंब न किया जाए और नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण कर ली जाय। उन्होंने ई-केवाईसी एवं अवशेष 18 यूनिटों पर आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए तथा किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जायेगी।

वृद्ध आश्रम में प्री–कैंप लघु विधिक सेवा एवं साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

- वृद्धि जनों को उनके अधिकारों की दी गयी जानकारी

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

कौशाम्बी। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को वृद्धा आश्रम में प्री-कैम्प/लघु विधिक सेवा एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव श्रीमती आस्था मिश्रा ने आश्रम में निवास कर रहे सभी वृद्धजनों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किये। शिविर के दौरान वृद्धजनों को उनके अधिकारों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन

योजना, आयुष्मान भारत योजना, वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने हेतु प्रेरित किया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इस अवसर पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री अमित मिश्रा एवं श्री तिलक नारायण, मध्यस्थ अधिवक्ता श्री मंदीप अवस्थी, पी.एल.वी. श्री कृष्णा कपूर तथा वृद्धा आश्रम के मैनेजर श्री आलोक राय सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। सभी ने वृद्धजनों की समस्याओं को सुनकर आवश्यक विधिक परामर्श प्रदान किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को जागरूक कर उन्हें न्याय एवं सरकारी सुविधाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना रहा।

कस्तूरबा विद्यालय में 'प्रगति 2.0' बाल उत्सव का आयोजन, बालिकाओं की प्रतिभा को मिला मंच

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

उन्नाव। विकासखंड सरोसी के ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बुधवार को 'प्रगति 2.0 स्वाभिमान और सफलता की ओर' थीम पर बाल उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार पांडे ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत खंड शिक्षा अधिकारी सिकंदरपुर सरोसी जगदीश कुमार एवं खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय संजय यादव द्वारा मुख्य अतिथि को बुके भेंट कर स्वागत के साथ हुई।

बालिकाओं के चौमुखी विकास पर जोर- उत्सव के दौरान बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें पोस्टर प्रतियोगिता, कॉमिक बुक प्रतियोगिता और 'कहानी मेरे बदलाव की' जैसी गतिविधियां प्रमुख रहीं। जनपद के सभी 16 विकासखंडों से बालक-बालिकाओं ने अपने-अपने नोडल शिक्षकों के साथ प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि बीएसए शैलेश कुमार पांडे ने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि शिक्षा ही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित किया। विजयी छात्र-छात्राओं को जिला समन्वयक बालिका शिक्षा चंद्रेश्वर मिश्र एवं जनपद नोडल अर्चना सिंह की अनुशंसा पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

तौरा का 50 शैय्या आयुष चिकित्सालय बना शोपीस

डॉक्टरों की गैरहाजिरी से मरीज परेशान

- 8 करोड़ की लागत से बना अस्पताल सिर्फ फार्मासिस्ट के सहारे, ओपीडी व्यवस्था ठप

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

बिछिया। क्षेत्र के तौरा गांव में करोड़ों की लागत से निर्मित 50 शैय्या का आयुष चिकित्सालय ग्रामीणों के लिए सुविधा के बजाय शोपीस बनकर रह गया है। सरकार की मंशा के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से यह चिकित्सालय बनाया गया था, लेकिन वर्तमान हालात यह हैं कि अस्पताल का संचालन केवल एक फार्मासिस्ट के सहारे किया जा रहा है।

मरीजों का कहना है कि अस्पताल में तैनात चिकित्सक अक्सर नदारद

रहते हैं। ओपीडी का नियमित संचालन नहीं होता और अधिकांश समय केवल फार्मासिस्ट ही दवा देकर मरीजों को लौटा देता है। इससे मरीज अपनी समस्या डॉक्टर को बता ही नहीं पाते और उन्हें उचित व सटीक इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

ग्रामीणों रामू, राघवेंद्र, प्रकाश चन्द्र, दीपांशु, चंद्रिका, दीपक, अमित, सुनील, सुशील, रमेश सहित करीब आधा सैकड़ा से अधिक मरीजों ने बताया कि चिकित्सकों के आने-जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है। जबकि अस्पताल में अधीक्षक डॉ. आशा वर्मा, डॉ. अल्का दीक्षित सहित यूनानी व होम्योपैथी के चिकित्सकों की तैनाती दर्शाई गई है, इसके बावजूद निरंतर ओपीडी नहीं चल रही है।

इस संबंध में आयुष चिकित्सालय की अधीक्षक डॉ. आशा शर्मा ने बताया कि अस्पताल में होम्योपैथिक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं।

अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, रक्त परीक्षण सहित कई प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध बताई गई थीं। इसके अलावा नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुष पंचकर्म जैसे उपचार तथा विशेष रूप से अर्श और भगंदर जैसी बीमारियों का क्षार सूत्र विधि से इलाज किया जाना था, लेकिन यह सभी सुविधाएं कागजों तक ही सीमित होकर रह गई हैं।

क्षेत्रीय और ग्रामीण लोगों को उम्मीद थी कि अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्हें दूर-दराज के सरकारी या निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आयुष चिकित्सालय से प्राकृतिक और प्रभावी उपचार मिलने की जो आस जगी थी, वह डॉक्टरों की अनुपस्थिति और अव्यवस्थाओं के कारण टूटती नजर आ रही है।

हमारा आंगन हमारे बच्चे' कार्यक्रम का किया गया आयोजन

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

पुरवा-उन्नाव। विकासखण्ड हिलौली की बीआरसी पर 'हमारा आंगन हमारे बच्चे' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौरावां के चेयरमैन कुंवर विवेक नारायण सेठ द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बेसिक शिक्षा विभाग तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में विकासखंड हिलौली के प्राथमिक विद्यालयों में कोलोकेटेड आंगनवाड़ी की कार्यकत्री एवं बच्चों ने तथा कक्षा 1 व 2 में पढ़ने वाले निपुण बच्चों ने प्रतिभाग किया। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा की। सीडीपीओ ने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एआरपी विनोद कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाल-वाटिका पर तथा आनंद कुमार ने माता उन्मुखीकरण पर चर्चा की। कार्यक्रम में अनुराग मिश्र, नीरज कश्यप, श्रीकांत तिवारी, दीपक उत्तम, सहदेव, वंदना कर्दम, अंजु अवस्थी, दीपा यादव आदि शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सरल कुमार द्वारा किया गया।

उत्तर रेलवे

ई ऑक्शन सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई ऑक्शन से सम्बंधित सूचना।

एकीन यूनिट / जोन	लखनऊ–उ०रे०–मण्डल– वाणिज्य / उ०रे०
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	PnU-LKO-PRG-WRL-101-24-1 (Pay & Use-Lounges/Waiting/Retiring/ Cloak Rooms)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	29.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	13.02.2026 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	13.02.2026 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	ADVT-LKO-LKO-OH-570-25-1 (Advertising out of home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	28.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	14.02.2026 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	14.02.2026 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	ADVT-LKO-MFKA-OH-628-26-1 (Advertising out of home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	28.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	14.02.2026 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	14.02.2026 समय 10:40 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	ADVT-LKO-BTKD-OH-629-26-1 (Advertising out of home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	28.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	14.02.2026 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	14.02.2026 समय 10:50 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	ADVT-LKO-UTR-OH-628-26-1 (Advertising out of home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	28.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	14.02.2026 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	14.02.2026 समय 11:10 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	ADVT-LKO-DYD-OH-626-26-1 (Advertising out of home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	28.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	14.02.2026 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	14.02.2026 समय 11:20 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	MSS-LKO-AME-MFC-139-25-1 (Misc-Static-Services -Multi Functional Complex)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	31.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	16.02.2026 समय 11:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	16.02.2026 समय 11:40 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	MSS-LKO-RBL-MFC-138-25-1 (Misc-Static-Services -Multi Functional Complex)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	31.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	16.02.2026 समय 11:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	16.02.2026 समय 13:00 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	ADVT-LKO-ON-OH-632-26-1 (Advertising out of home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	28.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	14.02.2026 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	14.02.2026 समय 11:30 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	ADVT-LKO-ON-OH-630-26-1 (Advertising out of home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	28.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	14.02.2026 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	14.02.2026 समय 11:40 बजे
नीलामी सूची सं० / लॉट सं०	ADVT-LKO-BSB-OSD-623-26-1 (Advertising on station (Digital)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	28.01.2026
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	14.02.2026 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	14.02.2026 समय 12:20 बजे
नीलामी का प्रकार	Close Ended
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है	E- Auction Module of www.ireps.gov.in

No: Va-V/ LKO DIV Publicity/CPRO/2025/KKG Dt. 10.02.2026 459/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

श्वेता मिश्रा के नेतृत्व में स्वच्छता और सुगम आवागमन की दिशा में बड़ा कदम

- दो वार्डों में नाली व इंटरलॉक सड़क का लोकार्पण, नागरिकों को मिली राहत

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

उन्नाव। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा द्वारा नगर के दो वार्डों में जनसुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण कर उन्हें क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया। इन कार्यों का उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ आवागमन को सुगम बनाना है।

कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड संख्या 06 सिविल लाइन्स से हुई, जहां राकेश शुक्ला के मकान से उन्नावऽहरदोई मुख्य मार्ग तक निर्मित नाली एवं इंटरलॉक सड़क का

लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सभासद मीरा आर्या उपस्थित रहीं। यह निर्माण कार्य क्षेत्र की जलनिकासी और यातायात व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके पश्चात वार्ड संख्या 17 मोतीनगर के मोहल्ला श्याम बिहार कॉलोनी में मुख्य मार्ग से अचल कुमार निगम के मकान तक बनी नाली एवं इंटरलॉक सड़क का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सभासद ब्रजेश पाण्डेय मौजूद रहे। इस कार्य से क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाओं का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई।

लोकार्पण कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता अचल निगम, विवेक मिश्रा, बबलू पाण्डेय, राम प्रकाश यादव, पंकज त्रिपाठी, अवधेश श्रीवास्तव, एम.पी. निगम, आशीष मिश्रा, ए.पी. निगम सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने कहा कि नगर के समग्र और सतत विकास के लिए नगर पालिका परिषद निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता और नागरिकों के सहयोग से ही विकास कार्यों को गति मिलती है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों के सहयोग और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया।

नगर पालिका परिषद द्वारा भविष्य में भी जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए नगर के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किए जाने की बात कही गई।

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

उन्नाव। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किए जाने के विरोध में बुधवार शाम शिक्षक संगठनों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के हालिया आदेश के खिलाफ नारेबाजी की और आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान एहतियातन पुलिस बल भी तैनात रहा।

उच्च न्यायालय के आदेश का दिया हवाला- प्रदर्शनकारी नेताओं ने बताया कि 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार देशभर के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। उनका आरोप है कि यह स्थिति भारत सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट में किए गए संशोधन के चलते उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय को यह आदेश देना पड़ा।

2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अलग थीं शर्तें- शिक्षकों का तर्क है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की सेवा शर्तें भिन्न थीं। उस समय नियुक्तियां बीटीसी और बीएड जैसी योग्यताओं के आधार पर की गई थीं। एक प्रदर्शनकारी नेता ने कहा, ल्लजो शिक्षक 20 से 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उनसे अब दो वर्षों के भीतर टीईटी पास करने को कहा जा रहा है। ऐसा न करने पर सेवा समाप्ति की बात कही जा रही है, जो अन्यायपूर्ण है।ङ्क उन्होंने इसे शिक्षक समाज के आत्मसम्मान पर आघात बताया।

केंद्रीय मंत्री से वार्ता का हवाला- प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस मुद्दे पर ऑल इंडिया फ़ेडरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत हुई थी। उनके अनुसार, मंत्री ने संशोधन में कमियों को स्वीकार करते हुए इसे सदन में संशोधित कराने का आश्वासन दिया था। हालांकि, 9 फरवरी 2026 को जारी आदेश में न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की बात कही गई, जिससे शिक्षकों में असंतोष और बढ़ गया है।

तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से अधिवक्ता घायल, कोतवाली में दी तहरीर

बांगरमऊ-उन्नाव। कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने ट्रक चालक के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ग्राम नौबतगंज मजरा जगतनगर निवासी आदित्य कुमार (एडवोकेट) ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि वह 8 फरवरी 2026 को आवश्यक कार्य से गंजमुरादाबाद गए थे। दोपहर करीब 1:20 बजे वापस लौटते समय अवध ढाबा के सामने उनकी मोटरसाइकिल में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े, जिससे उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल अधिवक्ता को उठाकर प्राथमिक उपचार दिलाया। पीड़ित ने बुधवार को कोतवाली में तहरीर देकर आरोपित चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

करसेमऊ में महाशिवरात्रि पर होगा विशाल गायत्री यज्ञ, भंडारा व आल्हा गायन

हसनगंज (उन्नाव)। विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत सिंघनापुर के राजस्व ग्राम करसेमऊ में स्थित ब्रह्मदेव बाबा मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। यहां विगत वर्ष ग्राम प्रधान तारावती पाल एवं जनसहयोग से महाशिवरात्रि के दिन प्राण प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग सहित गणेश, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, नंदी, हनुमान व शनि महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस शुभ अवसर पर 15 फरवरी को दिन में 12 बजे से विशाल गायत्री यज्ञ, भंडारा एवं भक्ति भाव से ओतप्रोत आल्हा गायन का आयोजन होगा। कार्यक्रम में स्मृति शेष लल्लू बाजपेई के शिष्य, लालगंज जनपद रायबरेली से पधार रहे आल्हा सम्राट जयशंकर त्रिवेदी द्वारा भक्ति रस से भरपूर आल्हा गायन प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान पुत्र पुत्तन लाल पाल ने क्षेत्रीय जनमानस से महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में दर्शन करने, यज्ञ-भंडारे में सहभागिता करने तथा आल्हा गायन का श्रवण करने हेतु ब्रह्मदेव बाबा मंदिर परिसर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की सादर अपील की है।

बिछिया ब्लॉक में एनआरएलएम कार्यालय बना शोपीस, महिलाएं लौट रहीं निराश

- कर्मी नदारद, रोज लटकता दिखता है ताला, बीडीओ ने दी यह सफाई

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

बिछिया। विकासखंड बिछिया स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कार्यालय में कर्मियों की अनुपस्थिति के चलते स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं लगातार परेशान हो रही हैं। जानकारी लेने या कार्य निस्तारण के लिए कार्यालय पहुंचने वाली महिलाओं को कोई भी जिम्मेदार कर्मी न मिलने से निराश होकर वापस लौटना पड़ता है।

ब्लॉक परिसर में बने एनआरएलएम कार्यालय पर प्रतिदिन ताला लटका नजर आता है। यहां

तैनात एडीओ आईएसबी मनोज कुमार की तैनाती बिछिया ब्लॉक में बताई जाती है, लेकिन ब्लॉक कर्मियों के अनुसार वे कभी कार्यालय में नजर नहीं आते। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर हरिओम भी नियमित रूप से ब्लॉक नहीं आते, जिससे फरियादियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

बताया गया कि बिछिया ब्लॉक के अंतर्गत चार क्लस्टरों में चार ब्लॉक मिशन मैनेजर–धीरेश निगम, अनीता सिंह, सोनम सिंह और संजय राजपूत की तैनाती है, लेकिन वे अधिकतर क्षेत्र स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इसी कारण ब्लॉक कार्यालय में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती और एनआरएलएम कार्यालय लगभग बंद ही रहता है।

एडीओ आईएसबी मनोज कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन रिसीव नहीं हुआ।

इस संबंध में खंड विकास अधिकारी फहद खान ने बताया कि एडीओ आईएसबी नवाबगंज ब्लॉक में भी सम्बद्ध हैं और संभव है कि इस समय एसआईआर कार्य में उनकी व्यस्तता हो।

डीएम ने किया ब्लॉक नकहा का औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप

- अलमारियों में कराए प्रॉपर इंडेक्सिंग, व्यवस्थाओं पर कसा शिकंजा
- स्टाफ और योजनाओं की स्थिति की बारीकी से की जाँच
- डीएम ने दस ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। बुधवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने विकास खंड नकहा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, अभिलेख व्यवस्था और योजना क्रियान्वयन की संपूर्ण समीक्षा की। डीएम ने सर्वप्रथम पीएम आवास, स्थापना एवं आवास पटल का निरीक्षण किया। अलमारियाँ खुलवाईं, अभिलेखों का अवलोकन किया और प्रत्येक फाइल की प्रॉपर इंडेक्सिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रखरखाव और दस्तावेज प्रबंधन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका भी जाँची गई। इसके बाद कार्यालय परिसर में शौचालय और आधार सेवा काउंटर की क्रियाशीलता भी जांची। गोढ़ी मजरा के नन्हें अर्नित (3) और विधि (5) का आधार नामांकन कराया जाता पाया गया। अभिभावकों से पूछताछ में पता चला कि कोई फीस नहीं ली गई। जिन आधार सेवाओं के लिए शुल्क नियत है, इसका डिस्प्ले भी मौके पर मिला। निरीक्षण के दौरान एसआईआर फीडिंग काउंटर पर ऑपरेटर दिव्यांशु फीडिंग करते मिले। डीएम ने नोटिस और अभिलेखों की बारीकी से जांच की और उपस्थित फीडिंग भी देखी। डीएम ने मौके पर अर्चना की नोटिस की फीडिंग संलग्न अभिलेखों की जांच की।

नोटिस के दौरान उपस्थित की फीडिंग भी देखी। इसके बाद एनआरएलएम कक्ष में जाकर स्वयं सहायता समूह, रिवाल्विंग फंड और एत्र्क्कसहित हर जरूरी जानकारी ली। समूहों की संख्या और उनकी सक्रियता पर भी निगाह रखी। डीएम ने ब्लॉक परिसर में मूलभूत सुविधाओं सहित वहां संचालित विभिन्न कार्यालय और पटलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। इसके बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बीडीओ कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली।

इस दौरान प्रमुख क्षेत्र पंचायत पवन गुप्ता, बीडीओ संगीता यादव सहित विकासखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने स्थापना, बजट, स्टोर, स्टाफ की स्थिति, पीएम और सीएम आवास योजनाओं की प्रगति और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका भी देखी। पीडी डीआरडीए को निर्देशित किया कि विकास खंडों में तैनात जिन कार्मिकों की डीपीसी पेंडिंग या कोई अन्य देयक लंबित हैं उन्हें नियमानुसार कराया जाए।

डीएम ने दस ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

विकासखंड में बैठक के दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बीडीओ संगीता यादव को निर्देशित किया कि विकास के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं करने वाली दस ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाए। डीएम ने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता विकास कार्यों की पूर्णता और पारदर्शिता है और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्राम तेन्धुआ में बुजुर्ग पर संदिग्ध हिंसक वन्यजीव का हमला, हालत गंभीर

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

गोला गोकर्णनाथ खीरी। वन रेंज मोहम्मदी की बिलहरी बीट अंतर्गत ग्राम तेन्धुआ-देवरिया में बीती रात एक बुजुर्ग पर किसी संदिग्ध हिंसक वन्यजीव द्वारा हमला किए जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी 75 वर्षीय रामपाल दीक्षित पर रात लगभग 3 बजे उस समय हमला हुआ, जब वह अपने घर में सो रहे थे। अचानक हुए हमले में वह लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा तत्काल सूचना दिए जाने पर सरकारी एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें सीएचसी गोला ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन दरोगा विजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बताया कि मकान के आसपास किसी बड़े हिंसक वन्यजीव के स्पष्ट पैरों के निशान नहीं मिले हैं, जिससे हमले के कारणों को लेकर जांच की जा रही है।घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और संभावित खतरे से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। वन विभाग द्वारा मामले की जांच जारी है।

गोला में निकली खाटू श्याम की भव्य निशान शोभायात्रा, श्रद्धालुओं पर हुई पुष्पवर्षा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

गोला गोकर्णनाथ खीरी। नगर में श्री खाटू श्याम महाराज बाबा की भव्य एवं विशाल निशान शोभायात्रा पूरे श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ धूमधाम से निकाली गई। श्याम समिति परिवार द्वारा आयोजित इस दिव्य आयोजन में रंग-गुलाल, भक्ति गीतों और गगनभेदी जयकारों के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए। छोटी काशी के नीलकंठ मैदान से श्रद्धाभाव के साथ निकली निशान शोभायात्रा में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से आए हजारों महिला-पुरुष श्रद्धालु हाथों में निशान ध्वज लेकर शामिल हुए। गुलाल उड़ाते, नाचते-गाते और जय श्री श्याम व जय श्री खाटू श्याम के नारों के साथ श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए, जिससे पूरा नगर श्याममय हो उठा। निशान शोभायात्रा मिल रोड, खुटार रोड, अलीगंज रोड, लखीमपुर रोड होते हुए मोहम्मदी रोड स्थित कंजा बाबा देवस्थान पहुंची, जहां स्थापित बाबा खाटू श्याम के मंदिर पर विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा का श्रद्धापूर्वक समापन किया गया। इस पावन अवसर पर नगर पंचायत मैलानी अध्यक्ष पति भवानी शंकर महेश्वरी की ओर से शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिससे भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। आयोजन के दौरान सेवा, समर्पण और अनुशासन का सुंदर समन्वय देखने को मिला। श्याम समिति परिवार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की श्रद्धालुओं ने सराहना की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

गन्ना बुवाई को अवैध बताने वाली नोटिस खारिज

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

- ऑर्डिनेटर गन्ना डॉ. दिनेश सिंह ने दी किसानों को राहत

गोला गोकर्णनाथ खीरी। जनपद खीरी में जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किस्म का गन्ना बताकर किसानों को दी गई नोटिस को अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (गन्ना) डॉ. दिनेश सिंह ने खारिज कर दिया है। उनके आदेश के बाद गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के अनुसार जिला गन्ना अधिकारी वेदप्रकाश द्वारा तीन किसानों को सीड एक्ट ऑर्डर 1966 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की नोटिस जारी की गई थी। यह नोटिस सांडा निवासी किसान गुरप्रीत सिंह, नवदीप सिंह एवं सिमरनजीत सिंह को उनके फार्म पर उगाई जा रही कुछ गन्ना प्रजातियों को अस्वीकृत बीज बताते हुए दी गई थी। नोटिस में को-17018, को-18022, को-86032, को-20016 एवं को-21012 प्रजातियों का उल्लेख किया गया था। नोटिस मिलते ही किसानों में हड़कंप मच गया।

घबराए किसानों ने भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। इसके बाद किसान नेता ने संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक को पूरे मामले से अवगत कराया। किसानों की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए धर्मेंद्र मलिक ने अगले ही दिन अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (गन्ना) डॉ. दिनेश सिंह से मुलाकात कर लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों की समस्या उनके समक्ष रखी। मामले की जांच के उपरांत डॉ. दिनेश सिंह ने जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अस्वीकृत बताई गई गन्ना प्रजातियों को स्वीकृत करार दिया और इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया।

पत्र में गन्ना प्रजाति को-17018, को-पीबी 17215, कोएस-16233, कोएस-17231, को-18022, को-पीबी 18213 एवं को-पी 16437 को किसानों द्वारा उगाए जाने के लिए स्वीकृत बताया गया है।

इस संबंध में भाकियू (अराजनैतिक) के जिला अध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन ने कहा कि ल्लमैं संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्ना किसानों को बड़ी राहत दिलाई। इस आदेश के बाद जनपद के गन्ना किसानों में खुशी का माहौल है।

संक्षिप्त समाचार

पुलिस ने तीन शातिर चोरों को दबोचा

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के थाना सुमेरपुर कस्बे के इमिलिया थोक में छापा मारकर मोबाइल टावर से केबिल काटकर चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को बुधवार को पुलिस ने जेल भेजा है। इनके पास से बरीपाल के टावर से चोरी की गई केबिल के साथ एक बाइक बरामद हुई है। इनमें बल्ला पाल उर्फ सियापाल का लंबा अपराधिक इतिहास है। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में नौ मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर नगर के सजेती थाना पुलिस ने सुमेरपुर कस्बे के इमिलिया थोक में छापा मारकर बल्ला उर्फ सिया पाल, सत्येंद्र यादव, शमशाद को दबोचा था। इनकी निशानदेही पर गत सोमवार को बरीपाल के मोबाइल टावर से चोरी की गई केबिल बरामद की गई। पुलिस ने चोरी की घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद किया है। सजेती थानाध्यक्ष अनुज भारती ने बताया कि तीनों शातिर चोर है। बल्ला उर्फ सिया पाल के खिलाफ 9 तथा सत्येंद्र के खिलाफ तीन मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। शमशाद के ऊपर यह पहला मुकदमा है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 12 फरवरी होगा खिलाड़ियों का चयन

हाथरस। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में अंडर-15 बालक एवं बालिका कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल कल 12 फरवरी 2026 को होगा।। ट्रायल आगरा राजमार्ग स्थित अखाड़ा भारत केसरी हरिकेश पहलवान कुश्ती एकेडमी में होगा। इसका उद्देश्य 17 से 19 फरवरी को वाराणसी के बाबतपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन करना है। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष राहुल जैसवाल और सचिव अंकित कुमार ने बताया कि 12 फरवरी को सुबह आठ बजे से नौ बजे तक पहलवानों का वजन लिया जाएगा।। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी।

सुलतानपुर की एसपी चारु निगम बोलीं-कानून से बड़ा कोई नहीं ड्रग, गोकशी, भू-माफिया व ट्रैफिक पर चलेगा अभियान

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने कहा कि अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रग माफिया, गोकशी गिरोह और भू-माफियाओं पर एक साथ कार्यवाही की जाएगी। ''कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वह अपराधी हो या विभाग का कोई व्यक्ति; कानून का उल्लंघन करने पर कार्यवाही तय है। पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने बुधवार को पुलिस लाइन के सभागार में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कानून व्यवस्था को लेकर अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, राजस्व और प्रशासनिक टीमों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि चिन्हित भू-माफियाओं की सूची तैयार की जा रही है और उनके खिलाफ गैंगस्टर सहित कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

एआई बता रहा पीएम आवास के लिए आवेदक पात्र है या नहीं

मुरादाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की नई सूची का सत्यापन पहली बार कृत्रिम बुद्धिमता (एआई-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से हो रहा है। इसी सूची के आधार पर मुरादाबाद समेत प्रदेश के सभी जिलों में गरीबों को पीएम आवासों का आवंटन किया जाएगा। करीब सात साल पहले बनी लाभार्थियों की सूची पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद अब एआई सत्यापित नई सूची तैयार की जा रही है। जिसके मार्च माह के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। जिससे प्रदेश के करीब ढाई लाख से अधिक गरीबों को आवास मिल पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए प्रदेशभर में पात्र लाभार्थियों का सर्वे वर्ष 2018 में कराया गया था। वर्ष 2019 में लाभार्थियों की स्थायी सूची तैयार की गई थी। इसी सूची के आधार पर अब तक ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा रहे थे लेकिन वर्ष 2024-25 तक यह सूची पूर्ण हो चुकी है।

जन्मदिन पर जनसेवा की मिसाल बने पलिया विधायक रोमी साहनी

- घायलों व जरूरतमंदों को 80 हजार की आर्थिक सहायता

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

कुकरा खीरी। पलिया विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विधायक रोमी साहनी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। उन्होंने विभिन्न गांवों में पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त, बीमार एवं जरूरतमंद परिवारों को उपचार हेतु कुल ?80,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की और दुख की घड़ी में उनका सहारा बने। जानकारी के अनुसार ग्रामसभा ग्रांट नं. 18 के गांव छत्तीपुर निवासी रिंकू गौतम (पुत्र रामभजन) के सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की सूचना पर विधायक रोमी साहनी स्वयं उनके घर पहुंचे और इलाज के लिए ?20,000 की सहायता दी। इसी क्रम में रामनिवास कोठिया के पुत्र के उपचार हेतु भी ?20,000 की आर्थिक मदद प्रदान की गई। वहीं ग्राम बगुली (ग्रामसभा संसारपुर) में कैंसर से पीड़ित राजेश गौतम (पुत्र बुधर लाल) को इलाज के लिए ?10,000 की सहायता दी गई। ग्राम दुर्जनपुर निवासी घायल राहुल गौतम (पुत्र पूरन लाल) को भी उपचार हेतु ?10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ग्राम त्रिकोलिया निवासी तारा देवी (पत्नी संतोष सिंह) के इलाज के लिए भी विधायक ने आर्थिक सहयोग दिया और आश्वस्त किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर वे सदैव साथ खड़े रहेंगे। ग्राम छब्बापुरवा (ग्रामसभा मझगई) में पुनीत कुमार को उनके पिता प्यारे लाल के इलाज हेतु ?10,000 की सहायता दी गई। साथ ही सिकंदरपुर में सुरेश (पुत्र रामचंद्र) के इलाज के लिए भी विधायक द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की गई।

इस अवसर पर विधायक रोमी साहनी ने कहा कि ल्लजनता की सेवा करना और उनके दुख-दर्द में साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है। क्षेत्रवासियों की हर संभव मदद के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत हजरतपुर एवं रोशननगर में विधायक रोमी साहनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता, प्रधान संघ के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, वहीदुल्ला खान, आफताब अंसारी सहित अनेक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

राजपथ पर चमकी गोरखपुर की एनसीसी कैडेट वंशिका सम्मानित

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज की छात्रा एवं 15 यूपी गर्ल्स बटालियन की एनसीसी कैडेट वंशिका ने नई दिल्ली में आयोजित 26 जनवरी 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर महाविद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। परेड से लौटने के बाद कॉलेज परिसर में हर्ष का माहौल है। महराजगंज जिले के बेलवा गांव की निवासी वंशिका बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित परेड में शामिल होने का अवसर मिला। राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी सहभागिता को महाविद्यालय परिवार ने गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वंशिका को महानिदेशालय एनसीसी, नई दिल्ली की ओर से आरडीसी मेडल, प्रमाण-पत्र तथा पीएम रैली मेडल प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से उन्हें प्रशस्ति प्रमाण-पत्र और उत्कृष्टता मेडल से भी सम्मानित किया गया।

महीनो से लगातार सड़क पर खुलेआम हो रहा जल भराव, ग्रामीणों को हो रही परेशानी

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

मलिहाबाद, लखनऊ। राजधानी क्षेत्र के ग्राम- अनीपुर में हर घर जल नल योजना के तहत बनवाई गई पानी की टंकी से लगभग तीन महीने से लगातार खुले सड़क पर खुलेआम जल भराव हो रहा जिससे ग्राम वासियों को आने जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणो ने जिलाधिकारी से अनुरोध कर रहे है की जल भराव होने से लोगों को परेशानी हो रही है जिसपे रोकथाम लगाए जाने की मांग की।

विकासखंड माल की ग्राम पंचायत अनीपुर में सरकार द्वारा हर घर जल नल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था जिससे सभी ग्राम वासियों के हर घर के सामने पाइपलाइन डालकर टोटी लगाई गई थी जिससे लगातार लगभग तीन महीने से टंकी का पानी खुले आम सड़कों पर भर रहा जिससे जल भराव कीचड़ युक्त हो जाने के कारण सभी ग्राम वासियों को आने-जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र के आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री 1076 कंप्लेंट दर्ज करने के बावजूद भी ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक तक कर्मचारी अधिकारी की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अंत मे ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मीडिया के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि जो टंकी का पानी सड़क पर खुलेआम भर रहा है इसको रोकथाम लगाई जाए समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है ।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने जगाई राष्ट्रवाद की अलख: कामेश्वर सिंह

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिला इकाई ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस क्रम में रानीडीहा स्थित भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी की अध्यक्षता में समर्पण दिवस पर जिला संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह रहे।

मुख्य वक्ता भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा के सामान्य परिवार में हुआ था, विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रप्रेम के भाव के साथ अपना सम्पूर्ण जीवन देश सेवा में समर्पित किया। तत्कालीन देश व पारिवार की विपरीत परिस्थिति होने पर भी उन्होंने राष्ट्रवाद की अलख जगायी। विषम परिस्थिति में देश व अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान, अन्त्योदय, उनका सेवा भाव व समर्पण हम सबके लिये प्रेरणा का विषय है।

उन्होंने कहा कि जनसंघ की जो कार्यपद्धति 1952 में बनी थी। आज वर्तमान में भाजपा उसी कार्यपद्धति को लेकर आगे चल रही है। आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय की संकल्पना को साकार कर रही हैं । आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था ही अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने कहा राष्ट्र तभी सशक्त बन पाएगा जब देश का कोई भी व्यक्ति रोटी कपड़ा और मकान के लिए भटके न।

राजापुर-नहर पटरी फोरलेन निर्माण में गड़बड़ी पर सीडीओ का कड़ा एक्शन

- सड़क खुदवाकर सैंपल जांच को भेजा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। जनपद में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दे दिया है। राजापुर से नहर पटरी तक बन रही फोरलेन सड़क में अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिषेक कुमार ने बुधवार को औचक निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी व संबंधित अधिकारियों पर सीधा एक्शन लिया। सीडीओ ने मौके पर पहुंचते ही औपचारिक निरीक्षण तक सीमित न रहते हुए सड़क की खुदाई कराई और निर्माण सामग्री के नमूने संग्रहित कराए। नमूनों को विधिवत सील कर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने सड़क पर ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि केवल कागजी रिपोर्ट और औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। गुणवत्ता को लेकर असंतोष जताते हुए सीडीओ ने सड़क निर्माण कार्य तत्काल रुकवा दिया और निर्देश दिए कि जांच रिपोर्ट आने व गुणवत्ता मानकों की पुष्टि के बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाए। सीडीओ के सख्त रुख से अधिकारियों और ठेकेदारों में खलबली मच गई।

निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड-1 के अधिशासी अभियंता के.के. झा को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि जांच में निर्माण गुणवत्ता मानकों से कम पाई जाती है तो अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई व आर्थिक पेनल्टी सुनिश्चित की जाए। साथ ही पूरे प्रकरण पर शीघ्र विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। सीडीओ अभिषेक कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा कि ल्लजनता के टैक्स के पैसे से बनने वाले विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर सड़क टिकाऊ, सुरक्षित और मानक अनुरूप होनी चाहिए। गुणवत्ता से समझौता करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्यों की सतत निगरानी, नियमित तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

भारत बनाम नामीबिया: अभिषेक की तबीयत खराब होने से मेजबान टीम चिंतित

एजेंसी

नयी दिल्ली। मौजूदा चैंपियन भारत को गुरुवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप मैच में नामीबिया से किसी तरह का खतरा नहीं है लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पेट के संक्रमण के कारण मुख्य कोच गौतम गंभीर सहित टीम प्रबंधन चिंतित होगा क्योंकि इससे उसकी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में वानखेड़े की चिपचिपी पिच पर बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें फिरोज शाह कोटला की पिच पर आक्रामक खेल दिखाना चाहेगा, जिसे बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच कहा जा सकता है। नामीबिया के खिलाफ भारत का पलड़ा बहुत भारी है जिसकी टीम इसी मैदान पर नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस तरह से देखा जाए तो भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले यह मैच अभ्यास मैच की तरह है। भारत अगर टॉस जीतता है तो वह पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा ताकि उसके बल्लेबाजों को पर्याप्त अवसर मिल सके। नामीबिया का गेंदबाजी आक्रमण खास नहीं है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रही कोई भी टीम उसको छठी का दूध याद दिला सकती है। भारत के लिए पेट के संक्रमण और वायरल बुखार के कारण अभिषेक का अस्पताल में भर्ती होना चिंताजनक है। भले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाए, लेकिन रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मैच से पहले उन्हें पूरी तरह से ठीक होने का मौका देने के लिए मैदान पर उतारना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस मैच में अभिषेक की मौजूदगी विपक्षी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित होगी। नामीबिया के खिलाफ मैच खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन के लिए लय में लौटने का एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार असफलताओं के चलते उन्हें अपनी जगह ईशान किशन के हाथों गंवानी पड़ी, जो इस समय शानदार फॉर्म में हैं। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा, ''संजू अच्छा महसूस कर रहे हैं और चोटिल खिलाड़ी के स्थान पर टीम में अपनी भूमिका को समझ रहे हैं। वह एक नेक इंसान हैं, टीम के साथ उनका व्यवहार अच्छा है, वह अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं और टीम में हम सभी से यही उम्मीद करते हैं। भारत की मजबूत बल्लेबाजी को रोकना नामीबिया के लिए कड़ी चुनौती होगी।

ओमान के खिलाफ श्रीलंका के मध्यक्रम के बल्लेबाजों को दिखाना होगा दम

एजेंसी

पल्लीकल। श्रीलंका की टीम गुरुवार को यहां जब टी20 विश्व कप के ग्रुप बी के मैच में ओमान का सामना करेगी तो उसकी निगाह अपनी बल्लेबाजी विशेषकर बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन करने और चोटिल वानिंदु हसरंगा के बाहर हो जाने के बाद नया गेंदबाजी संयोजन तैयार करने पर होगी। स्पिन गेंदबाज हसरंगा आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईसीसी के इस टूर्नामेंट से पहले श्रीलंका का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उसे इंग्लैंड से घरेलू श्रृंखला में 0-3 से करारी हार मिली थी। हालांकि टूर्नामेंट की सह-मेजबान टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 20 रन की जीत के साथ अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की। इस मैच में हालांकि उसकी स्पिन गेंदबाजी को खेलने की कमजोरी उजागर हो गई। आयरलैंड ने जब स्पिन गेंदबाज लगाए तो श्रीलंका के बल्लेबाज सातवें और 15वें ओवर के बीच एक भी चौका नहीं लगा सके। ओमान इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अगर कामिंदु मेंडिस ने आखिरी ओवरों में 19 गेंदों पर 44 रन बनाकर श्रीलंका को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक नहीं पहुंचाया होता तो हालात बदतर हो सकते थे। जहां कामिंदु ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाए वहीं कुसल मेंडिस ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए अर्धशतक लगाया। टीम को सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका और कामिल मिशारा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी जो अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में विफल रहे। हसरंगा ने आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने अपने चार ओवर पूरे किए और तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनकी जगह दुशान हेमंथा को टीम में शामिल किया गया है जिन्होंने अभी तक केवल पांच वनडे और तीन टी20 मैच खेले हैं। ऐसे में पहले मैच में भी तीन विकेट लेने वाले स्पिनर महेश थीक्षाना को अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी होगी। जहां तक ओमान का सवाल है तो उसे जिम्बाब्वे के खिलाफ आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। चौथी बार इस टूर्नामेंट में खेल रहे ओमान को तेज गेंदबाजी और अतिरिक्त उछाल के सामने संघर्ष करना पड़ा। कोलंबो में उसके शीर्ष पांच बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंचने में भी नाकाम रहे।

संक्षिप्त समाचार

नजरुल का यू-टर्न: खिलाड़ियों और बीसीबी ने भारत में नहीं खेलने का फैसला किया

ढाका। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने अब यू-टर्न लेते हुए कहा कि भारत में टी20 विश्व कप के मैच नहीं खेलने का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) और खिलाड़ियों ने लिया था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यह फैसला सरकार की सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित था। बांग्लादेश ने भारत में होने वाले अपने मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने नामंजूर कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड ने ली। आईसीसी में हालांकि बांग्लादेश को दंडित न करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश की टीम को बाहर करने से पहले आईसीसी के साथ असफल बातचीत के दौरान नजरुल ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सुरक्षा चिंताओं के कारण टीम को न भेजना बांग्लादेश सरकार का विशेषाधिकार है। 'क्रिकबज' से नजरुल के हवाले से कहा, ''विश्व कप में नहीं खेलने पर अफसोस का कोई सवाल ही नहीं है। यह फैसला बीसीबी और खिलाड़ियों ने देश के क्रिकेट की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा के लिए लिया। इससे पहला नजरुल ने 22 जनवरी को कहा था, ''मुझे लगता है कि हमें आईसीसी से न्याय नहीं मिला। हम विश्व कप में खेलेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से सरकार का फैसला है।

भारत के साथ व्यापार समझौते पर संशोधित दस्तावेज से व्हाइट हाउस ने ''कुछ दालों'' का जिक्र हटाया

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' ने अंतरिम व्यापार समझौते पर जारी संशोधित दस्तावेज में उन अमेरिकी उत्पादों की सूची से ''दालों'' का जिक्र हटा दिया है जिन पर भारत के शुल्क समाप्त करने या कम किए जाने की बात कही गई थी। व्हाइट हाउस ने ''अमेरिका और भारत ने की ऐतिहासिक व्यापार समझौते (अंतरिम समझौता) की घोषणा'' शीर्षक से एक दस्तावेज (फैक्ट शीट) सोमवार को जारी किया था। भारत और अमेरिका के पारस्परिक एवं लाभकारी व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के ढांचे की संयुक्त घोषणा के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने इसे जारी किया। इसमें समझौते की प्रमुख शर्तों को उल्लेख किया गया है जैसे कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं एवं अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त करेगा या घटाएगा। इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, ''कुछ दालें'', सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसमें साथ ही यह कहा गया था कि भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने तथा ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य क्षेत्रों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। व्हाइट हाउस ने हालांकि मंगलवार को जारी संशोधित दस्तावेज (फैक्ट शीट) में 'दालों' का जिक्र हटा दिया और भारत के लिए प्रयुक्त शब्द ''प्रतिबद्ध'' को बदलकर ''इरादा रखता है'' (इंटेंड्स) कर दिया गया है। संशोधित दस्तावेज में कहा गया है, '' भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं व अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त या कम करेगा जिनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे व प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन तथा स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसमें कहा गया है, '' भारत अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने और 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद का इरादा रखता है। व्यापार समझौते पर पिछले सप्ताह जारी संयुक्त बयान में उन वस्तुओं की सूची में ''दालों'' का कोई उल्लेख नहीं था जिनपर भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों के लिए शुल्क समाप्त या कम किए जाने की बात कही गई थी। संयुक्त बयान में कहा गया था, ल्ल भारत अगले पांच वर्ष में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान एवं उसके कलपुर्जे, बहुमूल्य धातु, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोकिंग कोयला खरीदने का इरादा रखता है। यह संयुक्त बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद आया। बातचीत के दौरान ''दोनों नेताओं ने पारस्परिक व्यापार पर अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति जताई और व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।

दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 2025 में रिकॉर्ड 9.52 करोड़ यात्रियों ने किया सफर

दुबई। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, 2025 में भी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 2025 में रिकॉर्ड 9.52 करोड़ यात्रियों ने इसके टर्मिनल से सफर किया, जो अमीरात की जारी आर्थिक तेजी को दर्शाता है। वैश्विक महामारी के बाद के वर्ष में हवाई अड्डे की गतिविधियों में तेज उछाल आया है। इसे वैश्विक यात्रा रुचि के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सबसे बड़े शहर दुबई में बढ़ते पर्यटन, व्यापार एवं रियल एस्टेट अवसरों से बल मिला है। दुबई में पिछले साल पर्यटकों की संख्या पांच प्रतिशत बढ़कर 1.96 करोड़ तक पहुंच गई। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र का हवाई अड्डा लंबी दूरी की विमानन कंपनी एमिरेट्स का केंद्र है जो अमीरात में 'दुबई इंक.' के नाम से जानी जाने वाली सरकारी व सरकार से जुड़ी कंपनियों के नेटवर्क को मजबूती देता है। दुबई एयरपोर्ट्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पॉल ग्रिफिथ्स ने कहा कि 2025 में दुबई अंतरराष्ट्रीय ने यह दिखा दिया, '' रिकॉर्ड यातायात अब कोई अपवाद नहीं बल्कि इसकी संचालन वास्तविकता का हिस्सा बन चुका है। दुबई हवाई अड्डे से 2024 में 9.23 करोड़ यात्रियों ने सफर किया था जबकि 2023 में यह आंकड़ा 8.69 करोड़ रहा। 2019 में वैश्विक महामारी से ठीक पहले यात्रियों की संख्या 8.63 करोड़ रही थी और 2018 में 8.91 करोड़ थी।

बांगड़ ने कहा, बेखौफ होकर खेलना जारी रखे भारत

नयी दिल्ली। पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने कहा कि भारत को टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ बल्लेबाजों की नाकामी का ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है और उसे अपना बेखौफ रवैया जारी रखना चाहिए जिसके कारण उसने काफी सफलता हासिल की हैं।

वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए अपने पहले मैच में भारत 13वें ओवर में 77 रन पर छह विकेट खो बैठा था, लेकिन फिर भी उसने अमेरिका पर 29 रन से जीत हासिल की। बांगड़ ने जिओ हॉटस्टार के एक कार्यक्रम में कहा,'' मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाजों को वानखेड़े में अमेरिका के खिलाफ जो हुआ उसका बहुत अधिक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि टी20 क्रिकेट में आजकल जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर जोखिम भरा हुआ है। उन्होंने कहा, ''किसी दिन जब दो-तीन विकेट गिर जाते हैं और आप फिर भी आक्रामक खेलना चाहते हैं, तो एक साथ कई विकेट गिर सकते हैं।

इटली के खिलाफ नेपाल की निगाह जीत दर्ज करने पर

एजेंसी

मुंबई। अपने पहले मैच में इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देने वाला नेपाल गुरुवार को यहां इटली के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप के मैच में जीत हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इटली की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है जबकि नेपाल ने 12 साल पहले इस टूर्नामेंट में पदार्पण किया था। उसने 2014 में हांगकांग और अफगानिस्तान को हराया था लेकिन उसके बाद नेपाल एक भी मैच नहीं जीत पाया है। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल तीन मौकों पर टेस्ट खेलने वाले देशों को हराने के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन आखिर उसे हार का सामना करना पड़ा था। वह 2024 में दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ एक रन से और बांग्लादेश से 21 रन से हार गय था। लेकिन पिछले रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ वह एक समय लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच गया था लेकिन आखिर में उसे चार रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद हालांकि नेपाल के क्रिकेटरों को सुर्खियां मिल गई हैं जिन्होंने अपने खेल में काफी सुधार किया है। नेपाल की टीम ने इस मैच में पूर्व चैंपियन इंग्लैंड को कड़ी चुनौती दी थी। उसे दर्शकों का भी भरपूर समर्थन मिला था और इटली के खिलाफ भी पूरी संभावना है कि दर्शक उसे पूरा समर्थन देंगे। कुशल भुर्टेल के रूप में नेपाल के पास शीर्ष क्रम में ऐसा बल्लेबाज है जो आक्रामक शुरुआत दे सकता है, वहीं दीपेंद्र सिंह ऐरी, कप्तान रोहित पौडेल और आरिफ शेख मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करते हैं। लोकेश बाम ने अपने आक्रामक स्ट्रोक प्ले से इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा उलटफेर करने की संभावना जगा दी थी। उन्होंने जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद जैसे कुशल गेंदबाजों को निशाने पर रखा था। नेपाल को हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने बीच के ओवरों में पर्याप्त चौके नहीं लगाए। उन्हें विकेटों के बीच दौड़ में भी सुधार करना होगा। दूसरी ओर इटली टूर्नामेंट के पहले मैच में स्कॉटलैंड से मिली 73 रन की करारी हार को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहेगा। इस मैच के दौरान इटली के कप्तान वेन मैडसेन के कंधे में भी चोट लग गई थी और पूरी संभावना है कि नेपाल के खिलाफ हैरी मैनेंटी टीम की कप्तानी करेंगे। इटली ने गेंदबाजी के सात विकल्पों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह उस टीम को रोकने में विफल रही जिसकी टूर्नामेंट से पहले की तैयारी आदर्श नहीं थी। बांग्लादेश को बाहर किए जाने के कारण स्कॉटलैंड को अंतिम समय में टूर्नामेंट में जगह मिली थी। नेपाल के खिलाफ इटली को अगर जीत दर्ज करनी है तो उसके सभी बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि पिछले मैच में उसके छह बल्लेबाज दोहरे अंक में भी नहीं पहुंच पाए थे।

एशियन चैंपियनशिप 2026: अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जीता कांस्य पदक

नई दिल्ली। भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला ने एशियन चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। बुधवार को खेले गए फाइनल में 23 वर्षीय अनीश ने 23 हिट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

कजाखस्तान के निकिता चिर्यूकिन ने 28 हिट्स के साथ रजत पदक जीता, जबकि जापान के योशियोका दाई ने 31 हिट्स के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। फाइनल के निर्णायक चरण से पहले तीनों पदक विजेता 21-21 हिट्स के साथ बराबरी पर थे। पेनल्टीमेट सीरीज में चिर्यूकिन ने पांच में से चार निशाने साधकर दबाव बनाया। इसके जवाब में दाई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए परफेक्ट सीरीज लगाई और बढ़त हासिल कर ली।

एफडीटीएल मानकों के पालन के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे: इंडिगो

एजेंसी

नयी दिल्ली। इंडिगो ने विमानन नियामक डीजीसीए को बताया है कि संशोधित पायलट ड्यूटी मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक परिचालन, 'रोस्टरिंग' और निगरानी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विमान कंपनी इंडिगो को दिसंबर में बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी व्यवधान के बाद नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। विमानन कंपनी को नए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) मानकों पर मिली अस्थायी छूट मंगलवार को समाप्त होने के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को बयान जारी कर कंपनी की ओर से दी गई प्रगति रिपोर्ट एवं आश्वासन की जानकारी दी। इंडिगो में परिचालन का अत्यधिक अनुकूलन, अपर्याप्त नियामक तैयारी, सिस्टम सॉफ्टवेयर समर्थन में कमियां एवं प्रबंधन संरचना और परिचालन नियंत्रण में खामियां उन प्रमुख कारणों में से थीं जिनके कारण व्यवधान उत्पन्न हुए, जिसके बाद डीजीसीए ने विमानन की शीतकालीन निर्धारित उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती भी की थी। इंडिगो के तीन से पांच दिसंबर के बीच 2,507 उड़ानें रद्द किए जाने की पृष्ठभूमि में, डीजीसीए ने संशोधित एफडीटीएल मानकों के क्रियान्वयन में कुछ ढील देने के लिए विमानन कंपनी के अनुरोध को 10 फरवरी तक का समय दिया था। डीजीसीए की ओर से बुधवार को जारी बयान के अनुसार, इंडिगो ने बताया है कि दिया गया समय समाप्त होने के बाद वह वैधानिक प्रावधानों के पालन और नौ अक्टूबर 2025 को स्वीकृत एफडीटीएल योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विमानन कंपनी ने कहा कि 11 फरवरी 2026 से स्वीकृत एफडीटीएल योजना के पूर्ण अनुपालन के लिए सभी जरूरी परिचालन, 'रोस्टरिंग' और निगरानी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। एफडीटीएल से जुड़ी छूट पायलट की रात्रिकालीन ड्यूटी अवधि और रात में विमान उतारने (लैंडिंग) से संबंधित थी। डीजीसीए ने कहा कि उड़ान संचालन को स्थिर करने के लिए दी गई दोनों छूटें निर्धारित शर्तों, प्रति घंटे उड़ान संचालन आंकड़े जमा करने तथा साप्ताहिक/पाक्षिक परिचालन प्रदर्शन रिपोर्ट सौंपने के अधीन थीं।

अकासा एयर के सह-संस्थापक प्रवीण अय्यर ने दिया इस्तीफा

नयी दिल्ली। अकासा एयर के सह-संस्थापक एवं मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी प्रवीण अय्यर ने इस्तीफा दे दिया है। विमानन कंपनी में चार महीने के भीतर वरिष्ठ स्तर पर यह दूसरा इस्तीफा है। अकासा एयर ने बुधवार को बयान में कहा कि पांच वर्ष की उल्लेखनीय यात्रा के बाद अय्यर ने अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया कि वह 30 अप्रैल 2026 तक नेतृत्व दल के साथ मिलकर का करेंगे। अय्यर, नीलू खत्री के बाद विमानन कंपनी छोड़ने वाले दूसरे सह-संस्थापक हैं। खत्री ने अक्टूबर 2025 में पद छोड़ा था। अकासा एयर के वर्तमान में चार सह-संस्थापक आदित्य घोष, आनंद श्रीनिवासन, बेलसन कुटिन्हो और भाविन जोशी हैं। अकासा एयर ने सात अगस्त 2022 से उड़ान संचालन शुरू किया था।

बजट राजस्थान: वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट किया पेश

एजेंसी

जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट (आय-व्ययक अनुमान) राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2026-27 में 21 लाख 52,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सदन की बैठक शुरू होते ही वित्त मंत्री ने राज्य के वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान विधानसभा में पेश किए। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, '' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा, '' विकसित राजस्थानअ2047 को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीत हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण एवं सुशासन को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने कहा, '' मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा किए गए ढांचागत सुधार व कुशल वित्तीय प्रबंधन से पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 21 लाख 52,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय भी 1.67 लाख रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर दो लाख के पार पहुंच जाएगी। अपने बजट भाषण में उन्होंने जलदाय विभाग में नई जल नीति लाने सहित अनेक घोषणाएं कीं।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में सभी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित : वाणिज्य सचिव

एजेंसी

न्यूर्नबर्ग (जर्मनी)। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौतों में हमेशा उन क्षेत्रों को लेकर ''स्पष्ट सोच'' रखी है जो देश के लिए ''बेहद'' संवेदनशील हैं और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते में ऐसे सभी प्रमुख क्षेत्रों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर काम कर रहे हैं जिसे मार्च के अंत तक अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। अग्रवाल ने यहां पत्रकारों से कहा, '' भारत ने हमेशा सभी समझौतों पर स्पष्ट सोच के साथ बातचीत की है। जो भी क्षेत्र भारत के लिए बेहद संवेदनशील हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे किसान, मछुआरे, दुग्ध क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, वहां हमने अपने साझेदार देशों को साफ बता दिया है कि भारत ऐसे मामलों में बाजार नहीं खोल सकता या पहुंच नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, '' अगर आप पिछले एक साल में किए गए सभी समझौतों को देखें। हमने पांच व्यापार समझौते किए हैं। सभी में संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की गई है। अमेरिका के साथ भी सभी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है। जहां थोड़ी संवेदनशीलता थी, वहां हमने शुल्क दर 'कोटा' व्यवस्था का इस्तेमाल किया ताकि बाजार तक पहुंच सीमित रहे और हमारे किसानों पर असर न पड़े। इस महीने की शुरुआत में घोषित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन वस्तुओं पर अमेरिका को कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है। ये उत्पाद संवेदनशील हैं क्योंकि इनका संबंध देश के छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका से है। अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भी भारत ने संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है। भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को अंतिम रूप दिया है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे पशुपालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनसे 50 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहां कृषि अत्यधिक मशीनीकृत और कॉरपोरेट आधारित है, वहीं भारत में यह आजीविका का सवाल है। भारतीय कृषि क्षेत्र को वर्तमान में घरेलू किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए मध्यम से उच्च शुल्क एवं नियामकीय उपायों के जरिये संरक्षण दिया गया है। भारत को 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। प्रमुख निर्यातों में बादाम (छिलके सहित, 86.8 करोड़ डॉलर), पिस्ता (12.1 करोड़ डॉलर), सेब (2.1 करोड़ डॉलर) और एथेनॉल (एथिल अल्कोहल, 26.6 करोड़ डॉलर) शामिल हैं। अग्रवाल यहां 'बायोफैच' 2026 प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं जहां 100 से अधिक भारतीय प्रदर्शक और करीब 20 राज्य अपने जैविक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरोपीय संघ इन उत्पादों का बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा, '' दल इस पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मार्च तक इसे (अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को) औपचारिक रूप दे दिया जाएगा। श्रम-प्रधान क्षेत्रों के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ यह समझौता भारत को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बढ़त देगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार में उन देशों पर भारत से अधिक शुल्क लगाया जा रहा है।

स्वामी मुद्रक प्रकाशक एवं सम्पादक हरिनाथ सिंह * द्वारा टिनटिन प्रिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड डी-33 अमौसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, नादरगंज, लखनऊ से मुद्रित एवं 1/39 प्रथम तल करामत मार्केट निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित, सम्पर्क-522-4064242

Email: noidarp@gmail.com, therptimes@yahoo.com, 9918735329 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

सूचना

पाठकों को सुझाव दिया जाता है, कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पहले स्वयं उचित जाँच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद या सेवा हेतु किये गये किसी दावें की सच्चाई का आश्वासन नहीं देता तथा ऐसे विज्ञापनों पर विश्वास करके किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति, हानि, परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

महाशिवरात्रि पर गौरा को लाने राजसी स्वरूप में बारात लेकर निकलेंगे काशीपुराधीश्वर

■ सिगोंल और नवरत्नों से सज्जित छत्र के साथ सिंहासन पर विराजेंगे महादेव,शिव-बारात में दिखेगा अनूठा लोकाचार

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

वाराणसी। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सदियों पुरानी लोक परंपराओं और आस्थाओं का जीवंत उत्सव है। इसी परंपरा के निर्वाह में इस बार महाशिवरात्रि पर काशीपुराधीश्वर महादेव माता गौरा को लाने के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप में सिगोंल (दंड) के साथ राजसी ठाठ-बाट में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस दौरान बाबा का विग्रह स्वरूप अन्य पर्वों से सर्वथा भिन्न और विशिष्ट होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ वर्ष में चार बार चल स्वरूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं, किंतु महाशिवरात्रि का नगर भ्रमण सबसे अलग और विशिष्ट माना जाता है। इस दिन काशीपुराधीश्वर माता गौरा के बिना, अकेले राजसी स्वरूप में अपने अढ़भंगी भक्तों और गणों के साथ दिखाई देते हैं।

काशी की प्राचीन लोकपरंपरा के अनुसार हर वर्ष सावन पूर्णिमा, दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले अन्नकूट महोत्सव और रंगभरी एकादशी के अवसर पर टेढ़ीनीम स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत आवास से बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा को विधि-विधानपूर्वक लाकर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया जाता है। इन तीनों अवसरों पर काशीपुराधीश्वर माता गौरा और प्रथमेश के साथ सपरिवार प्रतीकात्मक नगर भ्रमण में भक्तों को दर्शन देते हैं। लोकमान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ माता गौरा को लेने अकेले ही निकलते हैं। यही कारण है कि इस दिन बाबा का श्रृंगार, उनका वाहन, छत्र, सिगोंल और सिंहासन सभी कुछ विशेष रूप से तैयार किया जाता है। यह परंपरा शिव-विवाह की पूर्व संध्या का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें बाबा दूल्हे के रूप में गौरा को लेने निकलते हैं।

शिवाजंली के संयोजक संजीव रत्न मिश्र ने बुधवार को बताया कि इस वर्ष काशी की ऐतिहासिक शिव-बारात में काशीपुराधीश्वर का प्रतीकात्मक चल स्वरूप विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। बाबा नवरत्नों से सुसज्जित राजसी छत्र और सिंगोल के साथ 11 प्रकार की काष्ठ से बने भव्य सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। इन काष्ठों का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बताया जाता है, जो नवग्रहों का भी प्रतीक माने जाते हैं। बाबा के छत्र का निर्माण श्री काशी विश्वनाथ डमरू सेवा समिति के ओम शकर शर्मा ''मोनू बाबा और ''पागल बाबा'' ने कराया है।

अढ़भंगी भक्तों संग निकलती है शिव-बारात

महाशिवरात्रि की शिव-बारात काशी की सबसे अनूठी और जीवंत परंपराओं में से एक है। इसमें बाबा के साथ उनके अढ़भंगी, वैरागी, नागा साधु और गण शामिल होते हैं। ढोल-नगाड़ों, डमरुओं की नाद और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच निकलने वाली यह बारात श्रद्धा, उल्लास और लोकसंस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। महंत वाचस्पति तिवारी ने बताया कि काशी में महाशिवरात्रि का आयोजन केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे नगर की लोकचेतना में रच-बस जाता है। घर-घर में दीप प्रज्ज्वलन, व्रत-उपवास, शिवभक्ति और बारात के स्वागत की परंपरा निभाई जाती है। काशीपुराधीश्वर का यह प्रतीकात्मक नगर भ्रमण सदियों से चली आ रही उस लोक परंपरा का साक्ष्य है, जिसमें भगवान शिव को नगर का राजा और काशीवासियों को उनका परिवार माना जाता है। महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। बाबा के राजसी स्वरूप और ऐतिहासिक शिव-बारात के दर्शन के लिए देश-विदेश से भक्त काशी पहुंच रहे हैं। महंत परिवार और परंपराओं से जुड़े परिवारों द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

गंगा और भृगु मंदिर को जोड़ने वाला भव्य भृगु कॉरिडोर बनेगा

बलिया। काशी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर अब बलिया में भी महर्षि भृगु मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस दिशा में पहल करते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन के नेतृत्व में आर्किटेक्ट प्लानर की टीम द्वारा डिजिटल जियो पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से विस्तृत सर्वे किया जा चुका है। भृगु मंदिर समिति के सदस्यों और मंदिर के पुजारियों की उपस्थिति में कॉरिडोर की रूपरेखा और उसके सांस्कृतिक व पौराणिक महत्व को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एडीएम त्रिभुवन ने बताया कि सर्वे के दौरान तय किया गया कि भृगु कॉरिडोर में ददरी मेला स्थल, पवित्र गंगा नदी और भृगु मंदिर को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे कॉरिडोर का धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व और अधिक सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि भृगु मंदिर समिति एवं पुजारियों ने मंदिर के मुख्य गर्भगृह को यथावत रखते हुए शेष मंदिर संरचना का पारंपरिक सांस्कृतिक कला के अनुरूप जीर्णोद्धार तथा मंदिर परिसर के सुंदरीकरण पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही मंदिर परिसर के बाहर मुख्य सड़क के किनारे बने अवैध अतिक्रमण को हटाने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क के किनारे स्थित भूमि का विधिवत अधिग्रहण किया जाएगा, ताकि प्रभावित लोगों को नियमानुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर के चारों ओर के मार्गों को खोलते हुए भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। बुधवार को चित्रगुप्त मंदिर समिति एवं भृगु मंदिर समिति के साथ बैठक कर अंतिम सहमति बनाई गई। सभी पक्षों की सहमति के पश्चात भृगु मंदिर कॉरिडोर का आर्किटेक्ट डिजाइन तैयार कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद रेलवे को मिली ऐतिहासिक जीत

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे को सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक और निर्णायक जीत मिली है। लगभग 10 वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई में शीर्ष अदालत ने रेलवे प्रशासन के अधिकारों पर लगी न्यायिक आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह खारिज किया। भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) की वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण गौड़ द्विवेदी से जुड़े इस मामले में आया फैसला न केवल रेलवे के संस्थागत हितों की रक्षा करता है, बल्कि भविष्य में रेलवे प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए एक मजबूत कानूनी आधार भी तैयार करता है।

बता दें कि मामले की शुरूआत 30 सितंबर, 2016 को हुई, जब अंबाला के तत्कालीन रेलवे मजिस्ट्रेट ने अंबाला मंडल की तत्कालीन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण गौड़ द्विवेदी को एक अनुरोध भेजा, जिसमें औचक जांच के लिए एक समर्पित टिकट चेकिंग दस्ता देने का अनुरोध किया गया था। मंडल में विशेष महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए प्रवीन गौड़ द्विवेदी ने रेलवे मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि उस विशेष समय पर स्टाफ नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने एक हलफनामे के माध्यम से यह भी प्रस्तुत किया कि '' स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट दस्ते'' के लिए किसी भी स्वीकृत पद के अस्तित्व में न होने के कारण अनुरोध संभव नहीं है। उन्होंने भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 का हवाला देते हुए यह भी बताया कि टिकट चेकिंग स्वाभाविक रूप से एक कार्यकारी कार्य है। जिसमें स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट (एसआरएम) चेक वाणिज्य विभाग के समन्वय से नियमानुसार नियोजित किए जाने चाहिए न कि न्यायपालिका द्वारा एकतरफा मांगे जाने चाहिए।

आईपीसी की धाराओं के तहत शुरू की गई कार्यवाही

बता दें कि स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट ने टिकट चेकिंग दस्ता देने से इन्कार से असंतुष्ट होकर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि भारतीय दंड सहिता (ऋए) की धारा 186, 187 और 217 के तहत जोकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य में बाधा डालने और निर्देशों की अवज्ञा से संबंधित है, आपके विरूद्ध क्यों न कार्यवाही शुरू की जाए। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्विवेदी ने कानूनी लड़ाई जारी रखी।

सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत

बता दें कि महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, सचिव, रेलवे बोर्ड और प्रवीण गौड़ द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पेटिशन दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि यह कार्यवाही अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे एक ईमानदार अधिकारी को परेशान करने के बराबर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णायक फैसले में निचली अदालतों के विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और रेलवे अधिकारी के विरूद्ध चल रहे आपराधिक कार्यवाही को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां रेलवे मजिस्ट्रेट अपने ही मामले में जज बनना चाहते हैं। अपीलकर्ता ने अपने अधिकारिक क्षमता से बाहर कोई काम नहीं किया था। शीर्ष अदालत का यह फैसला न केवल लगभग 10 वर्षों से मानसिक परेशानियां झेल रही भारतीय रेल यातायात सेवा (ऋट्टट्ट) की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती प्रवीण गौड़ द्विवेदी को बरी करता है बल्कि यह एक कानूनी मिसाल भी कायम करता है कि ''स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट (ट्टटख्र) प्रशासनिक मांगों को लागू करने या कार्यकारी टिकट चेकिंग कार्यों की निगरानी के लिए अपराधिक कानून का हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते।''इस निर्णय से न केवल द्विवेदी को व्यक्तिगत न्याय मिला बल्कि रेलवे की कार्यप्रणाली, अनुशासन और प्रशासनिक स्वतंत्रता की जीत हुई। यह निर्णय भविष्य में किसी भी ईमानदार रेलवे अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अनावश्यक न्यायिक दबाव से सुरक्षा प्रदान करेगा।

संपादक मण्डल

संस्थापक/संरक्षक
संजीव श्रीवास्तव

प्रधान संपादक
हरिनाथ सिंह

सलाहकार संपादक
डॉ एमएए खान आईएएस (रि)
डॉ ओम प्रकाश आईएएस (रि)
आशुतोष रंजन
अनिल तिवारी
आर पी शुक्ल आईएएस (रि)
मेजर के किशोर
हरीशंकर शुक्ल पीपीएस (रि)

स्थानीय संपादक
दिनेश कुमार गर्ग

कार्यकारी संपादक
अभयानंद शुक्ल

आध्यात्मिक संपादक
राम महेश मिश्र

ब्यूरो चीफ
मनोज कुमार शुक्ला

स्टेट कोआर्डिनेटर
विपिन सोनी

संपर्क मुख्यालय
कार्यालय फोन नं.: 0522-4643988
www.rashtriyaprastavana.com
ई-मेल: noidarp@gmail.com

संपर्क कार्यालय
प्रधान कार्यालय: 1/39, प्रथम तल करामत मार्केट, निशातगंज, लखनऊ
प्रशासनिक कार्यालय: 61 ए, मानस नगर, जियामऊ, हज़रतगंज, लखनऊ

एकात्म मानववाद से समाज का समग्र विकास संभव : डॉ. राम माधव

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

कानपुर। वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था भी कई देशों में असंतुलन और असमानता को जन्म दे रही है। ऐसे में एकात्म मानववाद का सिद्धांत समाज के संतुलित और समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। युवा पं.दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को समझें और देश की उन्नति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत की संस्कृति स्वयं प्रकाशित होने के साथ-साथ दूसरों को भी आलोकित करने की क्षमता रखती है। यह बातें बुधवार को बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. राम माधव ने कही। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर गंभीर विमर्श हुआ। वक्ताओं ने कहा कि भारत का चिंतन कर्तव्य केंद्रित है, अधिकार केंद्रित नहीं, और अंतिम व्यक्ति का उत्थान ही दीनदयाल जी का मूल उद्देश्य था। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का विकास केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि धर्म आधारित नैतिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिलीप कुमार दुबे ने कहा कि भारत की चेतना दर्शन पर आधारित है। पं. दीनदयाल भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में देखते थे। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे उनके साहित्य का अध्ययन करें और विचारों को समझें। प्रांत संघ प्रचारक भवानी भीख तिवारी ने कहा कि पं. दीनदयाल ने देश के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्मरण कराने का कार्य किया। प्रतिकुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने के बावजूद ज्ञान के अपार भंडार थे। उन्होंने राष्ट्र की आत्मा को 'चिति' के रूप में परिभाषित किया और एकात्मता की कल्पना प्रस्तुत की। कार्यक्रम के माध्यम से न केवल पं. दीनदयाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, बल्कि उनके 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांतों पर विमर्श करते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।

राजनीतिक संत थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

सीतापुर। भारतीय जनसंघ के पुरोधा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीतापुर जिला पंचायत सभागार में एक संगोष्ठी व प्रदर्शनी में भी भाग लिया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि कार्यालय मंत्री व सीतापुर प्रवासी डॉ विमल सिंह रहे। डॉ विमल सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम सब के विचारों के उत्सर्जक महामानव थे, उन्होंने राजनीति में मर्यादा एवं सच्चाई का प्रतिपादन किया और अंत्योदय का मंत्र पालन करते हुए उन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संघर्ष किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों एवं प्रकृति के संरक्षण की बात करते थे और वह उस समय कांग्रेस की पाश्चात्य नीतियों का विरोध करते रहते थे । वे सच्चे मायने में एक राजनीतिक संत थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी ने उनके संपूर्ण जीवन चित्र व राजनीतिक संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक संघर्षों एवं उनकी आदर्शवादिता पर अपनी बात रखी गई। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक सुधाकर शुक्ला द्वारा किया गया।

इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं व जन सामान्य द्वारा अवलोकित किया गया। इससे पूर्व विकास भवन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पांजलि भी की गयी। प्रमुख रूप से इस अवसर पर विश्राम सागर राठौर, गोविंद भारती, संजय मिश्रा, जितेंद्र मेहरोत्रा, रमेश भार्गव दीपू, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, जया सिंह अमित तिवारी, रामप्रताप सिंह, सचिन मिश्रा, उदित वाजपेई, राजेश्वर रस्तोगी सहित पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे।

पं. दीनदयाल ने समाज को देखने की एकात्मवादी दृष्टि दी : प्रो. योगेन्द्र सिंह

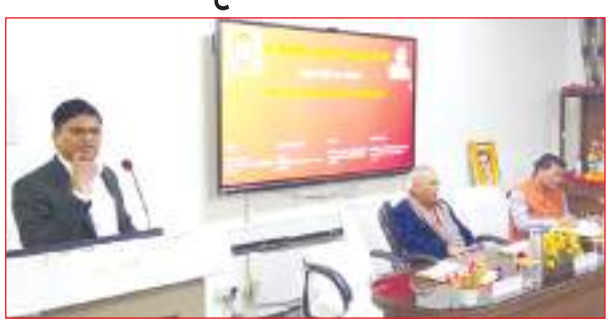

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के सभागार में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के तत्वावधान में पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार एवं सामाजिक दृष्टि विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह व्याख्यान का आयोजन हुआ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झूंसी प्रयागराज के निदेशक प्रो. योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि समाज को देखने की एकात्मवादी दृष्टि पं. दीनदयाल उपाध्याय ने दी। समाज को समझने की उनकी दृष्टि बहुत अभिनव है। उनके विचार हमारी समझ को बहुत व्यापक बना देते हैं। उन्होंने पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार एवं सामाजिक दृष्टि विषय पर सविस्तार सोदाहरण विचार प्रस्तुत करते हुए पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, लोकमत,जनमत, उदात्तीकरण परिष्कृति, प्राणवायु, गंगा जमुनी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर, सांस्कृतिक राष्ट्र, विकास, उन्नति, सत्यम, शिवम, सुंदरम, पाश्चात्य धर्म दर्शन, औपनिवेशिक विचार, जनजातिय समाज, एकात्म मानववाद, अंत्योदय आदि पर सविस्तार चर्चा करते हुए पं. दीनदयाल उपाध्याय की सामाजिक दृष्टि के लिए एक समेकित विचार की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि श्रमदान के स्थान पर श्रमानुभव किया जाए। गंगा -जमुनी तहजीब के आगे क्या होगा, इस पर विचार किया जाए। अध्यक्षीय उद्बोधन में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सत्यकाम ने कहा कि एकात्म मानववाद हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तम्भ है। भारतीय चिंतन परम्परा के अनुसार हमें अपनी सोच, साहित्य, समाज को बदलना होगा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी के विचारों से युवाओं का मार्गदर्शन करने पर बल दिया, जिससे युवा पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त हो सके। युवा पीढ़ी की रक्षा दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से ही संभव है। कुलपति ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार हमारे विश्वविद्यालय का भी ध्येय वाक्य होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परम्परा में पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार मील के पत्थर हैं।

ज्वाला देवी के प्रधानाचार्य ''मुख्यमंत्री अध्यापक सम्मान'' के लिए चयनित

■ शिक्षा जगत और काशी प्रांत में हर्ष की लहर

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की गौरवमयी शैक्षणिक परम्परा में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रयागराज के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान ''ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सिविल लाइंस'' के प्रधानाचार्य विक्रम बहादुर सिंह परिहार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ''मुख्यमंत्री अध्यापक सम्मान'' के लिए चुना गया है। इस घोषणा के साथ ही पूरे विद्या भारती काशी प्रांत और पूर्वी उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में उत्साह और गौरव का वातावरण व्याप्त है।

विद्यालय के मीडिया प्रभारी सरोज दूबे ने बताया कि यह सम्मान श्री परिहार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए वर्षों के अथक परिश्रम, नवाचारों और एक अनुशासित शैक्षिक वातावरण तैयार करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। उन्होंने न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाया, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को संस्कारों और आधुनिक कौशल से जोड़ने का भगीरथ कार्य किया है।

मूलतः मध्य प्रदेश के सतना जिले के गौनहारी गाँव के निवासी विक्रम बहादुर सिंह परिहार का जीवन सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और सैन्य अनुशासन का मेल है। उनके पिता नरेंद्र प्रताप सिंह परिहार भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात वर्तमान में कृषि के माध्यम से समाज सेवा में संलग्न हैं। सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से होने के कारण श्री परिहार की कार्यशैली में स्पष्ट निर्णय क्षमता और कठोर अनुशासन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी उच्च शैक्षणिक योग्यता उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और गहन ज्ञान को प्रमाणित करती है। विक्रम बहादुर सिंह परिहार की शैक्षिक यात्रा वर्ष 2007 में विद्या भारती योजना के अंतर्गत शक्ति नगर, सोनभद्र में वाणिज्य प्रवक्ता के रूप में प्रारंभ हुई थी। एक समर्पित शिक्षक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के बाद, उनके नेतृत्व कौशल को देखते हुए उन्हें प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपे गए। 2017 में ज्वाला देवी गंगापुरी में प्रधानाचार्य के रूप में प्रथम नेतृत्व संभाला। तत्पश्चात 2022 में सरस्वती विद्या मंदिर, सुलतानपुर में प्रधानाचार्य के रूप में संस्थान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वर्तमान में ज्वाला देवी सिविल लाइंस, प्रयागराज जैसे प्रमुख संस्थान का कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। सरोज दूबे ने बताया कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, उनके मार्गदर्शन में ''सेवा बस्ती'' क्षेत्रों में विशेष ''संस्कार केंद्र'' संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और नैतिक मूल्य प्रदान किए जा रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि यह प्रथम अवसर नहीं है जब श्री परिहार की सेवाओं को सराहा गया हो। इससे पूर्व भी उन्हें उनकी मेधा के लिए उपमुख्यमंत्री द्वारा ''सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान'', विभिन्न मंचों पर ''श्रेष्ठ प्रधानाचार्य सम्मान'' एवं अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों द्वारा विशिष्ट सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्या भारती के उच्च पदाधिकारियों, विद्यालय प्रबंधन समिति और समस्त विद्यालय परिवार ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। विद्या भारती काशी प्रांत के पदाधिकारियों ने कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उन आदर्शों का सम्मान है जिन्हें विद्या भारती आत्मसात करती है। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि भविष्य में प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी।